RNI No. DELMUL/2012/47011

11 जुलाई, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 100

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

किलियन एम्बाप्पे ने मिस्ड पेनल्टी की भरपाई 'गोल फॉर द एजेस' से की, फ्रांस को दिलाई बड़ी जीत 07

इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा, जिसमें करोड़ों लोग हुए शामिल

अयातुल्ला खामेनेई इमाम रजा दरगाह में हुए सुपुर्द-ए-खाक : 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा

वेब वार्ता, तेहरान

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को गुरुवार को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सात दिनों तक चले शोक कार्यक्रमों और अंतिम यात्रा में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। यदि यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से प्रमाणित होता है, तो इसे इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाएगा।

अंतिम संस्कार के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मशहद पहुंचे। इससे पहले तेहरान, कोम, नजफ, कर्बला और मशहद सहित कई शहरों में शोक सभाएं और अंतिम यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें भारी जनसैलाब उमड़ा। इस बीच, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई अंतिम संस्कार के दौरान सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के दौरान युद्ध की शुरूआत में उनके घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद पूरे ईरान में राष्ट्रीय शोक का माहौल रहा। धार्मिक स्थलों, सरकारी संस्थानों और प्रमुख शहरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

पूर्व के ऐतिहासिक अंतिम संस्कार

इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों की बात करें तो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरई के वर्ष 1969 में हुए अंतिम संस्कार में लगभग 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का उल्लेख मिलता है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान प्राप्त है। वहीं, ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खमैनी के वर्ष 1989 के अंतिम संस्कार में भी करीब 1.02 से 1.2 करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। अब जबकि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में उनके जनाजे को इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में शामिल करता है। हालांकि, इस संख्या की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है।

संक्षिप्त वार्ता

खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो सकते हैं मोजतबा खामेनेई

मशहद। अब ईरानी मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि मोजतबा खामेनेई जल्द ही कोम स्थित पवित्र दरगाह में अपने पिता की याद में आयोजित होने वाले एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो हमले के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक मौजूदगी होगी, हालांकि अभी तक ईरानी प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खामेनेई को जिस इमाम रजा दरगाह में दफनाया गया है, वह शिया समुदाय के आठवें इमाम का मजार है और यह ईरान का सबसे पवित्र व ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माना जाता है।

अयातुल्ला खामेनेई की मौत इसी वर्ष 28 फरवरी को एक बड़े हवाई हमले में हुई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध की शुरूआत हुई थी। इस हमले में उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी मारे गए थे। युद्ध की गंभीर स्थिति और सुरक्षा कारणों की वजह से उनके दफन का कार्यक्रम कई महीनों तक टलता रहा। आखिरकार शुक्रवार को हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें उनके पैतृक शहर में दफनाया गया, जहां अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग मातम मनाते नजर आए।

तिहाड़ जेल में विदेशी कैदी के नखरे, कहा नहीं खाऊंगा तीखा-मसालेदार खाना

नई दिल्ली। भारत की तिहाड़ जेल, जो बड़े से बड़े अपराधियों की अकड़ ठिकाने लगा देती है। इसी तिहाड़ में बंद अमेरिकी मर्सिनरी सैनिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइड ने जेल के खाने को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद से मैथ्यू एरॉन का नाम सुर्खियां में बना हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 13 मार्च 2026 को अमेरिकी मर्सिनरी सैनिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइड को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी कोलकाता एयरपोर्ट से की गई थी। मैथ्यू एरॉन के साथ ही छह यूक्रेनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था।

पुतिन का खतरनाक प्लानः यूक्रेन में शांति नहीं, अब और बढ़ेगा तनाव

मॉस्को। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल होती दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां शांति समझौते की बातें कर रहे हैं, वहीं क्रेमलिन से आ रही चौंकाने वाली खबरें बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश कर रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि युद्ध को नया रूप देकर और आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और ईंधन बुनियादी ढांचे पर बढ़ाए गए ड्रोन हमलों ने पुतिन के इरादों को और मजबूत कर दिया है।

मथुरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का गुंबद का हिस्सा गिरा

मथुरा। चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज के दौरान गुंबद का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि गिरा हुआ मलबा मस्जिद की ऊपरी छत पर ही आकर रुक गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

राम मंदिर के सीईओ के लिए डिग्री नहीं, भक्ति भाव जरुरी

चोरी पकड़ी जाने के बाद सीईओ की हो रही तलाश

वेब वार्ता, अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने प्रबंधन और व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) की तलाश शुरू कर दी है। हालिया दान विवादों के बाद लोगों का भरोसा कायम रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इस अहम भूमिका के लिए सिर्फ पेशेवर अनुभव या उच्च डिग्रियां ही पर्याप्त नहीं होंगी। सीईओ की तलाश के लिए गठित तीन सदस्यीय सर्च कमेटी के सदस्य सुरेश हावरे ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हावरे ने जोर दिया कि केवल पेशेवर क्षमता वाला व्यक्ति इस तरह के मंदिर का कुशल संचालन नहीं कर सकता। उनके अनुसार, पहली और सबसे आवश्यक शर्त राम के प्रति श्रद्धा का भाव है, जिसके बाद समाज के प्रति सेवा भाव और भक्तों के प्रति सम्मान का गुण आना चाहिए।

सुरेश हावरे ने बताया कि नया सीईओ मंदिर प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी होगा और उसके कंधों पर कई बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। इनमें प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ का सुगम प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन की देखरेख, और सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय प्रबंधन तथा खरीद-फरोख्त की व्यवस्था शामिल है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए सही व्यक्ति खोजने का काम ट्रस्ट द्वारा 6 जुलाई को गठित एक तीन सदस्यीय समिति को सौंपा गया है। अयोध्या के लिए एक अलग प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता पर बल देते हुए हावरे ने कहा कि यह सिर्फ एक नवनिर्मित मंदिर नहीं है, बल्कि इसके साथ 500 साल से अधिक का संघर्ष और हर हिंदू का भावनात्मक जुड़ाव है। यह आस्था और पहचान का प्रतीक है, जो इस जिम्मेदारी को कहीं अधिक बढ़ा देता है। उन्होंने जानकारी दी कि अयोध्या में रोजाना 2 लाख से अधिक भक्त आते हैं, और शुभ अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ एक सुव्यवस्थित मंदिर प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। हालिया दान विवादों के संदर्भ में हावरे का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज यह उम्मीद करता है कि हर दान का सटीक हिसाब रखा जाए और उसका जिम्मेदारी से उपयोग हो।

दतिया उपचुनावः भाजपा ने आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी

वेब वार्ता, भोपाल। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारते हुए लंबे समय से चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। पूर्व गृह मंत्री एवं दतिया से कई बार विधायक रह चुके डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अंततः आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया। गौरतलब है की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया जा रहा है। न्यायालय से दोषसिद्धि के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके चलते यह सीट रिक्त घोषित हुई और निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया। भाजपा में प्रत्याशी चयन को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार मंथन चल रहा था।

मोदी, मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा स्टेडियम

वेब वार्ता, नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में हजारों लोग जमा हुए। यह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विश्व नेता के लिए अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। मेलबर्न मीट्स मोदी नाम के इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम स्थल मोदी, मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम स्थल पर भारत का तिरंगा और ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहरा रहा है, जो दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी मजबूत संबंधों को दशार्ता है।

भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों ने भी पीएम मोदी के भाषण से पहले अपना उत्साह जाहिर किया। भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि सचमुच, मेलबर्न के दिल में इतिहास बनने जा रहा है। एक अन्य ने कहा कि मैं आज बहुत ज्यादा उत्साहित हूं और पीएम मोदी को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारतीय समुदाय के एक और सदस्य ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आज के शानदार भारत के पीछे वही हैं, उन्होंने कई तरह से भारत को आकार दिया।

बता दें इससे पहले दिन में पीएम मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया था, जब उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा शुरू की। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की तारीफ की और इसे सचमुच अविस्मरणीय बताया। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिले, जो ठंड के मौसम की परवाह किए बिना उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में वहां आए थे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को उनके गर्मजोशी भरे व्यवहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मेलबर्न में मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन भारतीय समुदाय से मिला गर्मजोशी भरा स्वागत सचमुच अविस्मरणीय था। उनका स्नेह और भारत के साथ अटूट बंधन हमेशा बहुत खुशी और गर्व का स्रोत रहा है।

चीन में जूतों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 28 की मौत

वेब वार्ता, बीजिंग

चीन के जिनजियांग शहर में एक जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कम से कम 28 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सामने आए वीडियो फुटेज में एक बहुमंजिला इमारत का अगला हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ, काले और सफेद धुएं से लिपटा हुआ दिख रहा है, जो आग की भयावहता को दशार्ता है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बचाव और राहत कार्यों के लिए पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के जिनजियांग शहर में एक संयुक्त कार्य दल भेजा।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आग दोपहर करीब 12 बजे लगी और तेजी से फैल गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को तलाश एवं बचाव अभियानों में हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने घटना के कारणों का तेजी से पता लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने तथा जवाबदेही तय करने के सख्त आदेश दिए हैं। जिनपिंग ने जांच में कोई ढिलाई न बरतने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

शहर के फायर डिपार्टमेंट के एक बयान के अनुसार, आग हुईटेंग शू कंपनी की एक फैक्ट्री में लगी थी। जिनजियांग को चीन की जूतों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस घटना का महत्व और बढ़ जाता है। आग लगने का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है, और यह भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि हाल के वर्षों में चीन में लगी सबसे जानलेवा आग में मरने वालों के अलावा और कितने लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ लोग छत पर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के प्रयास किए गए।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, बोलीं- करूंगी सरेंडर

गिरफ्तारी या मौत से नहीं डरती

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वह इसी वर्ष दिसंबर में अपने देश लौटेंगी और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि बांग्लादेश लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी।

शेख हसीना ने कहा कि वह देश की न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना है कि यदि कानून के तहत कार्रवाई होती है तो वह उसका सामना करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संभावित गिरफ्तारी या किसी हमले की आशंका के बावजूद वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का अपना निर्णय नहीं बदलेंगी।

शेख हसीना के इस बयान को बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके स्वदेश लौटने के ऐलान से देश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हालांकि, उनके इस बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार या संबंधित एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में भी घुस गए थे। इसके बाद वह बांग्लादेश वायु सेना के विशेष विमान से भारत पहुंचीं और तब से भारत में रह रही हैं।

इस बीच, बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध भारत को भेजा है। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस अनुरोध पर देश की न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप विचार किया जा रहा है।

मप्र में तय कोटे से 25% गिरा पानी, 32 जिलों में सामान्य से अधिक बरसे बादल

भोपाल, वेब वार्ता

मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश में अब तक निर्धारित बारिश का 25 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है। अब तक 234.4 मिमी (9.4 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 212.3 मिमी (8.3 इंच) की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों में पन्ना और सतना जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई माह में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जिससे बारिश का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। अगले चार दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

पन्ना और सतना जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भी बारिश का अनुमान है।

गुरुवार को भी कई जिलों में बरसे बादल

गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मंडला में लगभग पौन इंच वर्षा हुई, जबकि सिंगरौली में आधा इंच से अधिक और बालाघाट में करीब आधा इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बैतूल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना और सीधी में भी बारिश हुई।

जुलाई के नौ दिनों में बदली तस्वीर

जून महीने में आंधी और बारिश का दौर रहने के बावजूद प्रदेश में सामान्य से 30 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई थी। हालांकि जुलाई के शुरूआती नौ दिनों में हुई अच्छी बारिश ने यह कमी पूरी कर दी। अब प्रदेश में औसत से 10 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अब भी सामान्य से 9 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

राष्ट्रीय दैनिक
टाइम्स ऑफ़ पीडिया

संपादकीय

युद्धविराम के बाद युद्ध

अमरीका और ईरान के दरमियान कथित युद्धविराम 20–21 दिन ही टिक सका। अंततः बीती 8 जुलाई को तड़के 3–4 बजे ही ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर अमरीका ने ताबड़तोड़ हमले कर उसे दहला दिया। खौफ, अस्थिरता और संभावित हमलों की एक लहर ने खाड़ी देशों में झनझनाहट पैदा कर दी। जो सामान्य होने की उम्मीद कर रहा था, उसे असामान्य हालात में झोंक दिया। विश्व कांप उठा। बेशक ये हमले अप्रत्याशित, अनसोचे थे। पलटवार में ईरान ने भी दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन में करीब 85 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमला किया गया। ओमान की खाड़ी में मौजूद अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त किया। बहरीन और कुवैत में बिजली की लाइन पर ऐसा हमला किया गया कि इलाका अंधेरे में डूब गया। अमरीकी सेना ने होर्मुज के पास 3 शहरों पर हवाई हमले कर उन्हें दहला दिया गया, जबकि 10 से अधिक शहरों पर बम बरसाए गए। ईरान की महत्वपूर्ण बंदर अब्बास बंदरगाह की बिल्कुल तबाही की खबरें सामने आई हैं और वहां मौजूद कई जहाज क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। हमलों में ईरान की आईआरजीसी की 60 से अधिक पॉवर बोट्स को भी तबाह करने का दावा किया गया है। ईरान के सैन्य ठिकानों, वायु रक्षा प्रणाली, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन के ठिकानों पर अमरीकी हमले किए गए। बुशहर के परमाणु केंद्र के पास भी विस्फोट किए गए। सिरिक बंदरगाह और केश्म द्वीप के तेल ठिकानों पर भी मिसाइलें मारी गई। हमलों में 8 ईरानी सैनिक मारे गए, यह भी खबर है। सारांश यह है कि ईरान युद्ध का एक और चरण थोपा जा रहा है। यह अहंकार और विनाश का युद्ध है। अमरीका ही नहीं, इजरायल ने भी ईरान पर हमले बोलने की तैयारियां कर ली हैं। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नया खुलासा किया है कि ईरान के पास रासायनिक हथियार हैं। ऐसे ही आरोप अमरीका ने इराक के तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर लगाए थे कि इराक के पास जैविक, रासायनिक अस्त्र हैं, नतीजतन तबाही और मौतें व्यापक हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकला और सद्दाम को फांसी पर लटका दिया गया।

बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि युद्धविराम समाप्त हो गया है। उन्होंने ईरानियों को सनकी, धोखेबाज, झूठे, नीच, क्रूर आदि करार दिया है। ट्रंप ने ये अपशब्द अंग्रेजी में बोले हैं। कितना निचला स्तर है अमरीकी राष्ट्रपति का! ट्रंप का मानना है कि ईरान का नेतृत्व गलत हाथों में है, लिहाजा उससे बातचीत करना और समझौते की उम्मीद करना वक्त की बर्बादी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब वह ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ईरान कहर झेलने को तैयार रहे। हम ईरान के तटों को नरक बना देंगे। ट्रंप इतने अनिश्चित, अस्थिर हैं कि उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्धविराम के बाद युद्ध के उनके आदेश और ऐलान के बाद ही कच्चे तेल की कीमत 6 फीसदी उछल गई। अब तेल की कीमत करीब 79 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। दुनिया के लगभग सभी देशों के शेयर बाजार धड़ाम गिरे हैं। एकदम हाहाकार मचना शुरू हो गया है। यूरोपीय संघ ने परामर्श जारी किया है कि 31 अगस्त तक ईरान–इराक वायु क्षेत्र में उड़ान न भरें। ईरान ने होर्मुज फिर बंद करने का ऐलान किया है, तो अमरीका ने फिर नाकेबंदी का आदेश दिया है। ईरान पर से जो पाबंदियां समझौते के सहमति–पत्र के तुरंत बाद उठा ली गई थीं, 7 जुलाई से फिर उन्हें थोप दिया गया है। अमरीका के वित्त विभाग ने जो छूट दी थी, उसे रद्द कर दिया गया है और लाइसेंस खारिज कर दिए गए हैं। शांति के समझौते की नियति यही है। होर्मुज में करीब 350 जहाज–टैंकर फंस गए हैं, जिन पर करीब 6000 नाविक सवार हैं। भारत के भी 9 जहाज फंसे हैं, जिन पर 198 नाविक मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने सभी को सुरक्षित माना है। भारतीय मुद्रा ह्यरुपयाह्ण 63 पैसे टूटा है और एक डॉलर के मुकाबले 95 .59 रुपए हो गया है। ये हमले तब किए गए हैं, जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई पर मातम मना रहा है। अमरीका ने देर रात ईरान पर 150 हमले किए। प्रमुख चाबहार बंदरगाह पर भी हमला किया गया है। युद्ध पूर्णतः छिड़ चुका है। ईरान ने भी दावा किया है कि उसने कई देशों में स्थित अमरीका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान के एक नेता ने बताया कि होर्मुज को हम अपनी शर्तों पर खोलेंगे। इस मामले में अमरीका की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ईरान जब चाहेगा तो होर्मुज को खोला जाएगा। होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। जब तक यह शर्तें नहीं मानी जाती, होर्मुज बंद रहेगा।

मुफ्त दवा योजना पर संकट नहीं समाधान की जरूरत

जीवनरक्षक दवाओं की कमी गरीब मरीजों के लिए गंभीर चुनौती लेकिन समय रहते व्यवस्था सुधारकर सरकार भरोसा फिर मजबूत कर सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की खबरें सामने आई हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

गरीब और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदना हर परिवार के लिए आसान नहीं होता। विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए नियमित दवाएं जीवन का आधार होती हैं। यदि ऐसी दवाएं समय पर नहीं मिलें तो बीमारी बढ़ सकती है और आर्थिक बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि निशुल्क दवा योजना को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है।

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिन मरीजों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजा गया, कई दिनों बाद आने के लिए कहा गया या फिर बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी गई, उनकी परेशानी को सहज रूप से समझा जा सकता है। जो मरीज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचता है, उसके लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि दोबारा आने-जाने का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मरीजों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह इलाज कराए या परिवार का खर्च चलाए।

यह भी सच है कि यह समस्या केवल जयपुर तक सीमित नहीं दिखाई देती। प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर कुछ दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं सप्लाई में देरी होती है तो कहीं खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इससे सरकार की अच्छी योजनाओं की छवि प्रभावित होती है। जनता यह नहीं देखती कि कमी किस स्तर पर हुई है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अस्पताल पहुंचने पर दवा मिलनी चाहिए।

हालांकि इस पूरे विषय को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं का उल्लेखनीय

विस्तार किया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना जैसी पहल ने लाखों गरीब परिवारों को राहत दी है। यदि ये योजनाएं नहीं होतीं तो गरीब मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि योजना में कमी नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है।

अस्पताल प्रशासन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध नहीं हो पातीं तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है। कई बार आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से विलंब होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका समाधान भी प्रशासनिक स्तर पर संभव है। दवाओं की उपलब्धता का नियमित आकलन, समय रहते नई खरीद प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था से इस प्रकार की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में करोड़ों लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं है। दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और कई बार अनुमान से अधिक मरीज आने के कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल लापरवाही कह देना भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और दवा आपूर्ति एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे आवश्यक दवाओं का भंडार हमेशा सुरक्षित रहे।

तकनीक का बेहतर उपयोग भी इस दिशा में बड़ा समाधान बन सकता है। यदि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का ऑनलाइन स्टॉक रियल टाइम अपडेट हो तो यह पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में बची है और कब नई खेप की आवश्यकता होगी। इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। मरीजों को भी मोबाइल या हेल्पलाइन के माध्यम से यह जानकारी मिल सके कि संबंधित दवा किस अस्पताल में उपलब्ध है। इससे उन्हें अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ संवाद की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी है तो मरीज को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि दवा कब तक उपलब्ध होगी या उसका सुरक्षित विकल्प क्या है। कई बार जानकारी के अभाव में मरीज अधिक परेशान हो जाता है। संवेदनशील व्यवहार और स्पष्ट सूचना भी आधी समस्या का समाधान कर देती है। इस विषय में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल आरोप–प्रत्यारोप तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचानी चाहिए। जहां भी दवा की कमी हो, वहां तत्काल समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवा राजनीति का नहीं बल्कि मानवता का विषय है। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार के सामने यह अवसर भी है कि वह इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लेकर पूरे प्रदेश में दवा आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करे। जिन अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी है वहां तत्काल अतिरिक्त स्टॉक भेजा जाए। खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा तेज बनाया जाए। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, वहां जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा। अंततः किसी भी कल्याणकारी सरकार की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने से होती है। राजस्थान की निशुल्क दवा योजना लाखों लोगों के लिए वरदान रही है और इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि दवाएं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो गरीब मरीजों को न तो जेब से खर्च करना पड़ेगा और न ही इलाज अधूरा छोड़ने की मजबूरी होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं और उनका लाभ भी समाज को मिला है। अब आवश्यकता इस बात की है कि दवा आपूर्ति से जुड़ी कमियों को शीघ्र दूर किया जाए ताकि कोई भी मरीज केवल दवा की अनुपलब्धता के कारण पीड़ा न झेले। एक संवेदनशील और उत्तरदायी स्वास्थ्य व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की पहचान बनेगी, जहां इलाज के साथ भरोसा भी हर मरीज को समान रूप से प्राप्त हो।

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)
(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार–स्तम्भकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

अब यूजीसी नेट के पेपर लीक, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार

पेपर लीक होने का मामला थम नहीं रहा है। एक के बाद एक पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। सरकार हर बार बड़े-बड़े दावे करती है। हकीकत में पेपर इसके बाद भी लगातार लीक हो रहे हैं।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पेपर लीक होने का मामला उजागर किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सोशियोलॉजी का पेपर परीक्षा के पहले 2 लाख, 25 हजार में बेचा गया। इसके प्रमाण में राहुल गांधी ने हरियाणा के वकील दीपक धनखड़ की पीडीएफ फाइल अटैच की है। जिसमें पेपर लीक होने की जानकारी है। यह पेपर 2 लाख 25 हजार में परीक्षा के पहले बेचा गया। परीक्षा में वही पेपर आया। 6 जुलाई को ऑडियो संदेश के माध्यम से शिकायतकर्ता ने कहा पेपर लीक माफिया द्वारा वकील धनखड़ को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी तक उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने सुरक्षा मांगी है। राहुल गांधी ने अधिवक्ता दीपक द्वारा भेजी गई जानकारी को सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लिखा है, पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर भी लीक हुए हैं। यह काफी चौंकाने वाली खबर है। राहुल गांधी ने जो फाइल अटैच की है। पीडीएफ की फाइल नेशनल टेस्ट एजेंसी के पास ही उपलब्ध होती है। इसमें प्रश्न पत्र सेटिंग की सारी जानकारी उपलब्ध है।

भारत में पेपर लीक एक ऐसा मामला बन गया है जो कैंसर बीमारी की तरह है। कैंसर रोकने के जितने प्रयास किए जाते हैं, वह उसी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। यही हाल पेपर लीक मामले का है। इसको रोकने के बड़े-बड़े दावे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा परीक्षा लेने वाली एजेंसियों व संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। यह सब दावे हवा- हवाई साबित होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं। उन सभी के पेपर जानबूझकर लीक कराए जा रहे हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से अवैध रूप से लाखों रुपए परीक्षार्थियों से वसूल किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा परीक्षा एजेंसी के बीच एक अघोषित समझौता होता है, जिसके तहत परीक्षा किस तरह से करानी है, उसमें किस तरह से कमाई की जानी है। परीक्षा शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं। जिनका बंटवारा भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी और सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों के बीच में होती है। परीक्षाओं के माध्यम से अवैध रूप से पैसे लेकर अथवा विचारधारा के आधार पर चहेतों को परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा एजेंसी का चयन होता है। प्रश्न पत्रों को लीक करने से लेकर परीक्षा परिणाम तैयार करने व चयन एवं नियुक्ति तक में भारी गड़बड़ियां जानबूझकर की जा रही हैं। पेपर लीक रोक पाने के वास्तविक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पेपर लीक होने से कैसे रुकेंगे।

मात्र दो-तीन साल में सैकड़ो पेपर लीक हो चुके हैं। नीट यूजी परीक्षा में एडमिशन के लिए लाखों रुपए की वसूली की जाती है। उप्र की पुलिस भर्ती परीक्षा, महाराष्ट्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सेकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं। समय-समय पर खूब बवाल भी मचा। अभी छात्र जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रमुख समाज सेवी सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। जब भी पेपर लीक होते हैं। युवाओं में गुस्सा होता है। कुछ समय के बाद बात आई-गई खत्म हो जाती है। पेपर लीक होना कैसे बंद होंगे? जब पेपर कराने वाले ही पेपर लीक करा रहे हों। भारत की न्यायपालिका इस समय सरकार के दबाव में काम करते हुए दिखती है। सैकड़ो पेपर लीक होने के बाद भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान नहीं लेती है। जो मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं, उनकी सुनवाई फौरी तरीके से कर दी जाती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक के मामले को रोक सकती हैं। जब कोर्ट की निगरानी में सारे मामले की जाँच निष्पक्ष एजेंसी से हो। जांच के पश्चात दोषियों को दंडित करने का काम अदालतें कर पाती। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जिसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को न्यायपालिका द्वारा दंडित किया गया हो। जब तक परीक्षाओं से जुड़े राजनेता, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। तब तक पेपर लीक होने से रोक पाना भारत में संभव नहीं है। यही कहा जा सकता है।

लेखक- सनत जैन

पेट्रोल में एथनाल : आखिर ये माजरा क्या है?

भारत में इन दिनों पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किये जाने यानी ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाले नुक़्सान को लेकर बहस छिड़ गयी है। इसके प्रयोग से देश भर से वाहनों के इंजन खराब होने की खबरें मीडिया में आने लगी हैं। ई20 उपभोक्ता अब न केवल इसकी शिकायतें करने लगे हैं बल्कि जगह जगह इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी होने लगे हैं। गत दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ई20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया गया।और इससे वाहनों को होने वाले नुक़्सान को लेकर सरकार को अवगत कराया गया।

भारत में हो रहे इसके विरोध व इसके इस्तेमाल से आ रही परेशानियों व वाहनों को हो रहे कथित नुक़्सान की खबरों के बीच पड़ोसी देश भूटान ने भी भारतीय तेल कंपनियों से एथनाल मिश्रित ई 20 पेट्रोल वहां न भेजने व केवल पूर्व में भेजा जा रहा केवल शुद्ध ढ100 जैसे पेट्रोल की आपूर्ति करने को कहा है। भूटान द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर भण्डारण के पुराने भूमिगत फ़्यूल टैंक में ई 20 पेट्रोल के भण्डारण की वजह से पानी के रिसाव का जोखिम है जिससे एथनाल मिश्रित ईंधन खराब हो सकता है। क्योंकि इथेनॉल की प्रवृति नमी को आकर्षित करने वाली होती है और वातावरण से नमी लेने पर ईंधन की गुणवत्ता घट सकती है और इंजन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में स्टोरेज और सप्लाई श्रृंखला को आधुनिक करना भी आवश्यक होगा, जिसमें तत्काल परिवर्तन करना जोखिमपूर्ण माना गया। भूटान द्वारा अपनी आपत्ति में पहाड़ी रास्तों में वाहन के परफार्मेंस पर भी फर्क पड़ने का संदेह व्यक्त किया गया है।

भारत में भी देश भर से गाड़ियों के खराब होने,गाड़ियों की पेट्रोल टंकी के गलने व जंग लगने,माइलेज कम होने व इंजन के खराब होने तक की शिकायतें आने लगी हैं। और उधर इसी ई 20 पेट्रोल की आपूर्ति व खपत की आड़ में शुद्ध पेट्रोल यानी एक्सपी100 का मूल्य 167 रुपए प्रति लीटर तक हो गया है। एथनाल के उपयोग से केवल गाड़ियां ही खराब नहीं हो रही हैं बल्कि इसके उत्पादन में भी पानी का भी बेतहशा दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे भविष्य में यह जलसंकट का कारण भी बन सकता है। गौरतलब है कि एथनॉल का उत्पादन चावल ,मक्का और गन्ना आदि की फसलों से होता है। और इन सभी फसलों की पैदावार में बेतहाशा पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब इसी फसल से एथनॉल बनाया जाता है तो इसमें और भी ज्यादा पानी खर्च होता है। मिसाल के तौर पर चावल से 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 10790 लीटर पानी खर्च होता है जबकि मक्का से 1 लीटर एथनॉल बनाने में करीब 4670 लीटर पानी की खपत होती है इसी तरह गन्ने से मात्र 1 लीटर एथनाल बनाने में तकरीबन 3630 लीटर पानी लगता है। गोया पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की नीति देश के जल बचाने के अभियान के ठीक विरुद्ध जलसंकट खड़ा करने में भी सहायक हो सकती है। जरा सोचिये कि जब ई20 पेट्रोल की आपूर्ति में जल का इतना इस्तेमाल होता है तो यदि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की इच्छानुसार पेट्रोल में 85 प्रतिशत मिश्रण कर ई85 की आपूर्ति की योजना पर अमल किया गया तो भारत जैसे उस देश में पानी के अकाल को कैसे टाला जा सकेगा जहां के कई इलाकों में पहले ही पीने का पानी लोगों को मयस्सर नहीं है? हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब ई25 पेट्रोल को लागू करने की योजना को फिलहाल टाल सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस ई25 बदलाव को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

देश में पेट्रोल में एथनाल के मिश्रण को लेकर कुछ जिम्मेदार लोगों के विरोधाभासी बयान भी सुनाई दे रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों में एथनाल के मिश्रण के प्रति अविश्वास व भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्युटिव वाईस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने अपने एक इंटरव्यू में पहले तो यह स्वीकार किया था कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से बेशक फ़्यूल एफि शिएंसी में कुछ कमी आती है। परन्तु बाद में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन ईंधन भी बता डाला। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बायोफ़्यूलस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी ने भी स्वीकार किया था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों की माइलेज में 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने गत 30 जून को सर्वोच्च न्यायलय में एक सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया कि ई–20 पेट्रोल का इस्तेमाल फिलहाल एक प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद तो लोगों में और भी आक्रोश फैल गया कि आखिर प्रयोग के तौर पर उन्हें गिनी पिग अर्थात प्रयोग किये जाने वाला जीव क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से कही जा रही बातें गलत हैं।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी एक तरह से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की बातों का समर्थन करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि 3.6 करोड़ भारतीय कार मालिकों पर इसतरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि अभी भारत में 10 में से 9 गाड़ियां ई20 के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति आम सहमति के बिना और इसके होने वाले परिणामों को समझे बगैर लागू कर दी गई है। खड़गे ने यह भी कहा, हमारी गाड़ियों में इसे जबरदस्ती डालने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन बदलने की इस प्रक्रिया को प्रयोग नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जब सरकार का अपना डेटा ही अभी तक तैयार नहीं है, तो नागरिकों को नुक़्सान साबित करने की चुनौती नहीं दी जा सकती। आम लोग गिनी पिग नहीं हैं न ही हमारी सड़कें टेस्ट ट्रैक हैं और देश के उपभोक्ताओं की जेबें सरकार के ट्रायल का बजट नहीं हैं। खड़गे ने ई20 को वापस लेने मांग करते हुये कहा कि सरकार पहले इसे प्रयोग के योग्य,स्वीकार्य व प्रमाणित ईंधन साबित करे, फिर इसे प्रयोग करने की नीति लागू करें। निश्चित रूप से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण देश के वाहन धारकों के लिये फिलहाल एक समस्या बन गया है और सरकार द्वारा इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों व विशेषज्ञों व इस नीति के आलोचकों द्वारा उठाये जा रहे बिंदुओं के बीच देश समझ ही नहीं पा रहा है की आखिर ये माजरा क्या है?

लेखिका– निर्मल रानी

आलेख

कटती जमीन, उजड़ते गांवः गंगा कटाव पर कब बनेगी राष्ट्रीय नीति?

गंगा भारतीय सभ्यता की जीवनरेखा है। इसकी धारा ने सदियों से खेतों को उपजाऊ बनाया, शहरों को बसाया और करोड़ों लोगों की आजीविका को सहारा दिया। लेकिन यही गंगा आज बिहार के दियारा क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए हर वर्ष भय, असुरक्षा और विस्थापन का कारण बन रही है। मानसून के साथ नदी का बढ़ता कटाव सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि, मकानों और लोगों की जीवनभर की कमाई को निगल जाता है। बाढ़ का पानी कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन कटाव से उजड़े परिवारों का दर्द वर्षों तक नहीं मिटता। यही कारण है कि गंगा का कटाव केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट है।

बिहार में बाढ़ पर हर साल चर्चा होती है, राहत पैकेज घोषित होते हैं और बचाव कार्यों की समीक्षा भी होती है। इसके विपरीत गंगा कटाव का संकट अक्सर सीमित प्रशासनिक कार्रवाई तक सिमट जाता है। जिन किसानों की पुश्तैनी जमीन नदी में समा जाती है, उनके लिए न तो पर्याप्त पुनर्वास की व्यवस्था है और न ही कोई दीर्घकालिक नीति। परिणामस्वरूप हर मानसून हजारों परिवार इस आशंका में जीते हैं कि अगला नंबर कहीं उनके घर या खेत का न हो।

मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, भोजपुर, पटना, लखीसराय और सारण सहित गंगा के किनारे बसे अनेक जिले वर्षों से इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। नदी का बदलता प्रवाह खेतों, बगीचों और आबादी वाले इलाकों को लगातार काटता हुआ आगे बढ़ता है। इससे केवल भूमि का नुकसान नहीं होता, बल्कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है, उनके सामने जीवन का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

बिहार के मुंगेर जिले के सदर प्रखंड का टीकारामपुर इस समस्या का जीवंत उदाहरण है। यहां पिछले कई वर्षों से ग्रामीण स्थायी कटावरोधी उपायों की मांग कर रहे हैं। हाल के महीनों में कटाव की रफ्तार इतनी तेज हुई कि बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि गंगा में समा गई। कई किसानों की खड़ी फसलें देखते-ही-देखते नदी की भेंट चढ़ गईं और अब नदी गांव की आबादी के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लोगों के सामने केवल आर्थिक नुकसान का नहीं, बल्कि अपने घर-बार से विस्थापित होने का वास्तविक खतरा खड़ा है ।दियारा क्षेत्र में भूमि केवल खेती का साधन नहीं होती, बल्कि परिवार की पहचान, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का आधार भी होती है। जब कोई किसान अपनी जमीन खोता है, तो उसके साथ उसकी आय, सामाजिक स्थिरता और अगली पीढ़ी की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। इसलिए गंगा कटाव को केवल जल संसाधन विभाग या आपदा प्रबंधन का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और आजीविका से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है ।गंगा के कटाव को केवल प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम मान लेना वास्तविकता से आंखें मूंद लेने जैसा होगा। नदी का स्वाभाविक प्रवाह, तलछट का जमाव और धारा का बदलना अपनी जगह है, लेकिन अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है। कई स्थानों पर बिना समग्र अध्ययन के कराए गए तट संरक्षण कार्य, अवैज्ञानिक तटबंध, अनियंत्रित बालू खनन और पर्यावरणीय असंतुलन ने नदी के स्वभाव को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक स्थान पर किया गया कटावरोधी निर्माण कई बार नदी की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ देता है, जिससे दूसरे गांव खतरे की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए गंगा जैसी विशाल नदी के लिए स्थानीय नहीं, बल्कि समग्र नदी बेसिन प्रबंधन की आवश्यकता है ।बिहार में समय-समय पर पत्थर पिचिंग, स्पर निर्माण और तट संरक्षण जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। कुछ स्थानों पर इनसे अस्थायी राहत भी मिली, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। इसका कारण यह है कि गंगा का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। ऐसे में केवल इंजीनियरिंग आधारित समाधान पर्याप्त नहीं हैं। नदी विज्ञान, जल प्रवाह, तलछट और बदलती जलवायु को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी, तभी तट संरक्षण के प्रयास टिकाऊ साबित होंगे। कटाव का सबसे बड़ा असर किसानों और भूमिहीन मजदूरों पर पड़ता है। जिनकी जमीन नदी में समा जाती है, वे सरकारी अभिलेखों में भले ही भूमिधर बने रहें, लेकिन उनके पास खेती के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति में रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और आवास का संकट एक साथ खड़ा हो जाता है। मजबूरी में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं और शहरों में असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पर काम करने को विवश हो जाते हैं। इस तरह गंगा का कटाव केवल भूगोल नहीं बदलता, बल्कि गरीबी और सामाजिक असमानता को भी गहरा करता है ।कटाव प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की मौजूदा व्यवस्था भी कई सवाल खड़े करती है। अधिकांश मामलों में सरकारी प्रयास तत्काल राहत और मुआवजे तक सीमित रह जाते हैं, जबकि स्थायी पुनर्वास, कृषि योग्य भूमि, वैकल्पिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि विस्थापित परिवार वर्षों तक असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन बिताने को मजबूर रहते हैं। यदि आपदा प्रबंधन को वास्तव में प्रभावी बनाना है, तो राहत आधारित सोच से आगे बढ़कर पुनर्वास आधारित नीति अपनानी होगी ।गंगा के कटाव को केवल प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम मान लेना वास्तविकता से आंखें मूंद लेने जैसा होगा। नदी का स्वाभाविक प्रवाह, तलछट का जमाव और धारा का बदलना अपनी जगह है, लेकिन अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। जल विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात की ओर संकेत करते रहे हैं कि फरक्का बैराज के निर्माण के बाद गंगा में गाद (सिल्ट) के जमाव और नदी की धारा के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। अनेक अध्ययनों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि बढ़ते सिल्टेशन के कारण कई स्थानों पर नदी का प्रवाह अस्थिर हुआ है, जिससे तटों पर कटाव की तीव्रता बढ़ी है। इसके साथ ही अनियंत्रित बालू खनन, अवैज्ञानिक तटबंध और बिना समग्र अध्ययन के कराए गए कटावरोधी कार्यों ने भी समस्या को और गंभीर बनाया है। इसलिए समाधान किसी एक स्थान पर तटबंध खड़ा करने में नहीं, बल्कि पूरे गंगा बेसिन के वैज्ञानिक प्रबंधन में निहित है ।मुंगेर जिले के टीकारामपुर में वर्षों से चल रहा जनआंदोलन इस पीड़ा का प्रतीक बन चुका है। समाजसेवी राकेश कुमार मंडल, नागेंद्र सिंह त्यागी और उनके साथ जुड़े ग्रामीण लगातार गंगा पूजन, एकदिवसीय उपवास और शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से सरकार का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करते रहे हैं। उनका कहना है कि हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद स्थायी कटावरोधी व्यवस्था नहीं बन पाई है। ग्रामीणों की मांग है कि अस्थायी उपायों के बजाय वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर टिकाऊ तट संरक्षण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यापक योजना लागू की जाए ।कटाव का सबसे बड़ा असर किसानों और भूमिहीन मजदूरों पर पड़ता है। जिनकी जमीन नदी में समा जाती है, वे सरकारी अभिलेखों में भले ही भूमिधर बने रहें, लेकिन उनके पास खेती के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति में रोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का संकट एक साथ खड़ा हो जाता है। मजबूरी में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं और शहरों में असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पर जीवन बिताने को विवश हो जाते हैं। इस तरह गंगा का कटाव केवल भूगोल नहीं बदलता, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने–बाने को भी गहरा आघात पहुंचाता है।

गंगा केवल बिहार की नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय नदी है। इसलिए उसके कटाव से जुड़ी समस्या का समाधान भी केवल राज्य सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। आवश्यकता केंद्र और राज्य के साझा सहयोग से ऐसी दीर्घकालिक नीति बनाने की है, जिसमें वैज्ञानिक संस्थानों, जल संसाधन विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी हो। नदी के प्राकृतिक प्रवाह का सम्मान करते हुए तट संरक्षण, गाद प्रबंधन और पुनर्वास को एकीकृत दृष्टि से देखने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गंगा कटाव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नदी नीति के व्यापक ढांचे में शामिल किया जाए। कटावग्रस्त क्षेत्रों का नियमित वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, आधुनिक तकनीक से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाए और समय रहते प्रभावी तट संरक्षण कार्य शुरू किए जाएं। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले कटावरोधी कार्यों का स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन भी अनिवार्य होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खर्च के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। कटाव से प्रभावित परिवारों के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। जिन किसानों की पूरी जमीन गंगा में समा चुकी है, उनके लिए सम्मानजनक पुनर्वास, वैकल्पिक कृषि भूमि अथवा रोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा की समग्र व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि अभिलेखों के अद्यतन, मुआवजा निर्धारण और पुनर्वास की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना भी उतना ही आवश्यक है। स्थानीय समुदायों के अनुभवों को भी नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दियारा क्षेत्र के लोग पीढ़ियों से गंगा के स्वभाव को समझते आए हैं। यदि उनके अनुभवों को वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जोड़ा जाए, तो अधिक प्रभावी और टिकाऊ समाधान विकसित किए जा सकते हैं। नदी प्रबंधन केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि सरकार, विशेषज्ञों और समाज की साझी जिम्मेदारी है। गंगा भारतीय संस्कृति में आस्था, जीवन और समृद्धि की प्रतीक है। विडंबना यह है कि उसी गंगा के किनारे रहने वाले हजारों परिवार हर वर्ष अपने घर, खेत और भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास का अर्थ केवल सड़क, पुल और भवन बनाना नहीं है; विकास तब सार्थक होगा, जब गंगा किनारे रहने वाला किसान भी यह विश्वास कर सके कि हर मानसून उसके जीवन की नई परीक्षा नहीं बनेगा। अब समय आ गया है कि गंगा को केवल श्रद्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समझ और मानवीय संवेदना के साथ देखा जाए। यदि समय रहते ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं बनी, तो हर वर्ष उपजाऊ भूमि नदी में समाती रहेगी, गांव उजड़ते रहेंगे और विस्थापन की यह त्रासदी और गहरी होती जाएगी। गंगा की धारा को विकास की धारा बनाए रखना है, तो उसके किनारे बसे लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना ही होगा।

लेखक– कुमार कृष्णन

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली में महिलाओं की निःशुल्क बस यात्रा के नियम बदले

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की नि:शुल्क बस यात्रा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम ने नया परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा का लाभ केवल उन महिलाओं और तृतीय लिंग यात्रियों को मिलेगा, जिनके पास गुलाबी सहेली परिचय पत्र होगा। इसके साथ ही वर्तमान में प्रचलित कागजी गुलाबी यात्रा पर्ची व्यवस्था को 31 जुलाई के बाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार, 1 अगस्त से महिलाओं को बस में प्रवेश करते समय अपने गुलाबी सहेली परिचय पत्र का उपयोग करना होगा। यह व्यवस्था दिल्ली परिवहन निगम तथा समूह बसों, दोनों पर समान रूप से लागू होगी। परिचय पत्र नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को सामान्य किराया देकर यात्रा करनी होगी, क्योंकि 31 जुलाई के बाद कागजी गुलाबी यात्रा पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

चंदा विवाद पर केजरीवाल का नया अभियान

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर अपने आंदोलन को नया स्वरूप देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में सुंदरकांड का सामूहिक पाठ आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोहिणी के सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में सुबह 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके उपरांत भगवान का आशीर्वाद लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ भी आयोजित करेंगे।

पुर्णिया कोर्ट के लिए चल रही विशेष रेलगाड़ी की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से पुर्णिया कोर्ट के बीच चल रही विशेष रेलगाड़ी की अवधि को आगामी दो अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गाड़ी संख्या 05579 पुर्णिया कोर्ट से प्रत्येक शुक्रवार और रविवार (31 जुलाई तक) को चलकर आनंद विहार टर्मिनल आएगी। वहीं गाड़ी संख्या 05580 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक रविवार और मंगलवार को चलकर पुर्णिया कोर्ट जाएगी।

नजफगढ़ स्विमिंग पूल हादसे में नया मोड़

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित भोली राम पब्लिक स्कूल के तैराकी कुंड में 26 वर्षीय राहुल राय की डूबने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि तैराकी कुंड का संचालन करने वाली संस्था के पास आवश्यक वैधानिक अनुमति और लाइसेंस था या नहीं। वहीं, मृतक के परिजनों ने साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद तैराकी कुंड के आसपास लगे निगरानी कैमरे रातोंरात हटा दिए गए। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों और परिजनों ने घटना से संबंधित दृश्य अभिलेख देखने की मांग की, तब विद्यालय प्रबंधन और तैराकी कुंड संचालित करने वाली संस्था के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि वहां कोई निगरानी कैमरा लगा ही नहीं था।

जलभराव से निपटने को सरकार सतर्क

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जायस ने कहा है कि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने दावा किया कि राजधानी में संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

विनोद जायस ने बताया कि सरकार ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पूरे शहर में 200 रखरखाव दल तैनात किए हैं। प्रत्येक संवेदनशील स्थान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर यातायात का मार्ग परिवर्तित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही पंप चालू करने की व्यवस्था की गई है।

ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान: छह महीने में 48 लाख से ज्यादा चालान, आठ सड़कें बनीं सिग्नल-फ्री

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुरक्षित, स्मार्ट और सुगम बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस वर्ष कई बड़े कदम उठाए हैं। सड़कों पर जाम कम करने से लेकर सिग्नल-फ्री कॉरिडोर विकसित करने, आधुनिक तकनीक के जरिए चालान करने, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने तक कई मोर्चों पर काम किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि इन प्रयासों से राजधानी में यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

छह महीने में 48.42 लाख चालान, 17 लाख से ज्यादा ई-चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर 48,42,953 चालान जारी किए गए हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 47,52,173 थी। इसके अलावा रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन और ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन जैसी तकनीक आधारित प्रणालियों के माध्यम से 17,21,221 ई-चालान जारी किए गए। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों

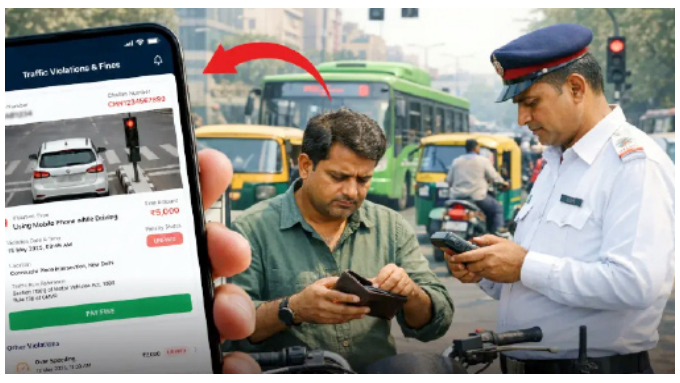

में 2,187 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

आठ प्रमुख सड़कें बनीं सिग्नल-फ्री

यात्रा का समय कम करने और जाम से राहत दिलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में आठ प्रमुख मार्गों को सिग्नल-फ्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। इनमें छह कॉरिडोर उत्तरी रेंज और दो पूर्वी रेंज में विकसित किए गए हैं। इन मार्गों पर अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाए गए, यू-टर्न की व्यवस्था की गई, अवैध मीडियन कट बंद किए गए और चौराहों का पुनर्गठन किया गया। इससे ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर हुआ और लोगों की यात्रा अधिक सुगम बनी। एनएसपी से रिठाला मेट्रो स्टेशन और विकास मार्ग (लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़) जैसे मार्गों पर इसका सकारात्मक असर साफ दिखाई देने लगा है।

कई बड़े जाम वाले इलाकों में मिला समाधान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनएचएआई, डीएमआरसी और डीटीसी जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर शहर के कई संवेदनशील ट्रैफिक प्वाइंट पर सुधार कार्य कराए। आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर

मानसून में जलभराव से निपटने की विशेष तैयारी

बरसात के मौसम में ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2025 में जलभराव वाले 169 स्थानों की सूची संबंधित एजेंसियों—एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए—को पहले ही उपलब्ध करा दी थी। हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान आयरन ब्रिज-वजीराबाद, गाजीपुर, आनंद पर्वत, लिबासपुर अंडरपास, जीटीके रोड और पांडव नगर अंडरपास जैसे संवेदनशील इलाकों से पानी तेजी से निकालकर यातायात सामान्य कराया गया। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छह डिजास्टर मैनेजमेंट वाहन भी तैनात किए हैं, जिनमें मोटर पंप और पेड़ काटने की मशीनें लगी हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य किया जा सके।

पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित ढांचा और अतिरिक्त बस बे बनाए गए। मजनू का टीला में फुट ओवरब्रिज बदला गया। खजूरी फ्लाईओवर से डीटीसी बसों का डायवर्जन किया गया। अधचिनी गांव और आश्रम चौक पर बस स्टैंड स्थानांतरित किए गए। आईएसबीटी आनंद विहार में पिक-अप और ड्रॉप जोन तथा अतिरिक्त बस पार्किंग की व्यवस्था की गई। वहीं कालिंदी कुंज पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इन कदमों से कई स्थानों पर ट्रैफिक दबाव कम हुआ है।

प्रोजेक्ट संगम से आम लोग बने ट्रैफिक व्यवस्था के भागीदार

उल्लेखनीय है कि तीनअप्रैल को उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट संगम के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आरडब्ल्यूए और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ मिलकर स्थानीय ट्रैफिक समस्याओं का समाधान शुरू किया।

अब तक 309 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 514 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से 368 सुझावों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 146 सुझाव संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। इस परियोजना के तहत द्वारका के एलिफेंट चौक-यूईआर-2 जंक्शन पर सड़क डिजाइन में बदलाव, वेस्ट पटेल नगर में ई-रिक्शा स्टैंड का स्थान परिवर्तन तथा आजादपुर के पास जीटीके रोड पर नए टी-पॉइंट के निर्माण से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल ने वर्ष की पहली छमाही में बड़े पैमाने पर जनजागरूकता अभियान चलाया। 1 जनवरी से 30 जून 2026 के बीच 2.84 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। इसके अलावा 15.44 लाख से अधिक नागरिकों तक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंच बनाई गई। 12 हजार से अधिक ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों, 11 हजार से ज्यादा डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर, 5,300 से अधिक कॉर्पोरेट कर्मचारियों, आरडब्ल्यूए सदस्यों, एनसीसी कैडेट्स और व्यावसायिक वाहन चालकों को भी सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान हेलमेट पहनने, लेन अनुशासन, नशे में वाहन न चलाने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, मिशन जीरो डेथ ऑन रोड, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और नो हॉर्निंग जैसे अभियानों को भी विशेष रूप से चलाया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी से 30 जून 2026 के दौरान ड्यूटी के दौरान 14 ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हुए।

रेखा गुप्ता ने मांडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का गडकरी से किया आग्रह

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली के महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को श्री गडकरी को पत्र लिखकर 8.8 किलोमीटर लंबे इस रणनीतिक सड़क कॉरिडोर के विकास का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मांडी रोड छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास महरौली-गुरुग्राम रोड (एनएच-148ए) को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। यह मार्ग दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतर-राज्यीय वाहनों की आवाजाही इसी सड़क से होती है। इसलिए इस सड़क का उन्नयन और बेहतर प्रबंधन समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की गवर्निंग बॉडी ने 27 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी 68वीं बैठक में मांडी रोड के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके चौड़ीकरण और व्यापक विकास के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि सड़क के रणनीतिक महत्व, वर्तमान और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-148ए से इसके सीधे जुड़ाव को देखते हुए इसे एनएचएआई के अधीन लाना उपयुक्त होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इसके विकास की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी जाए, ताकि एकीकृत योजना, समान इंजीनियरिंग मानकों और समयबद्ध तरीके से इस महत्वपूर्ण सड़क का उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा, दिल्ली-एनसीआर की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

अलीपुर में देर रात दो गोदामों में लगी आग, घंटों चला दमकल का अभियान

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर इलाके में गुरुवार देर रात दो गोदामों में आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दोनों गोदाम इसकी चपेट में आ गए। गोदामों में रखा भारी मात्रा में फॉयल पेपर और कार्डबोर्ड रोल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली दमकल विभाग के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात करीब एक बजे अलीपुर स्थित वाली गली के गली नंबर-10 में एक गोदाम में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली।

इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय, मुकेश गोयल समेत 15 सदस्य हुए शामिल

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। शुक्रवार को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक मुकेश गोयल समेत पार्टी के 15 सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सभी पार्षदों को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक मुकेश गोयल, हेमचंद तथा अन्य पार्षदों का भाजपा परिवार में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चार इंजन की सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय पूरी दिल्ली के लिए शुभ संकेत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता सुख भोगने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा की सेवा करने का मंच है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण तथा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से असंतुष्ट होकर पिछले वर्ष कुछ पार्षदों ने अलग होकर मुकेश गोयल के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया था। अब उनका भाजपा परिवार में शामिल होना पार्टी की विचारधारा और विकास कार्यों पर विश्वास का प्रतीक है।

साथ ही दिल्ली में जलभराव की स्थिति पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हाल की दो बारिशों के दौरान राजधानी में कहीं भी अधिक जलभराव की समस्या देखने को नहीं मिली।

फर्जी दस्तावेज से मैड्रिड पहुंचा भारतीय, केस दर्ज

फर्जी दस्तावेज के सहारे स्पेन जाने के आरोप में हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी 24 वर्षीय रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। रवि को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के दौरान फर्जी पोलिश रेजिडेंट परमिट के साथ पकड़ा गया।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

स्पेनिश इमिग्रेशन अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच में फजीर्वाड़ा सामने आने पर उसे देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया और इनएडमिसिबल यात्री के रूप में भारत वापस भेज दिया। सात जुलाई की रात रवि कतर एयरवेज की उड़ान से दिल्ली पहुंचा, जहां एयरलाइंस कर्मचारियों ने उसे आईजीआई एयरपोर्ट के डिपोर्टी सेल को सौंप दिया। जांच के दौरान भारतीय अधिकारियों को स्पेन इमिग्रेशन की रिपोर्ट मिली, जिसमें स्पष्ट किया गया कि रवि द्वारा प्रस्तुत पोलिश रेजिडेंट परमिट फर्जी था। स्पेनिश अधिकारियों ने मूल दस्तावेज जब्त कर लिया, जबकि उसकी प्रति भारतीय एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रवि तीन जुलाई को दिल्ली से मैड्रिड के लिए रवाना हुआ था।

आरोप है कि उसने इसी फर्जी पोलिश रेजिडेंट परमिट के आधार पर भारतीय इमिग्रेशन जांच पार कर विदेश यात्रा की। इस मामले में आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी का पासपोर्ट, यात्रा रिकॉर्ड, इमिग्रेशन लॉग, फर्जी रेजिडेंट परमिट की प्रति और एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज जांच में शामिल किए हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि रवि को फर्जी पोलिश रेजिडेंट परमिट कहां से मिला और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई ट्रैवल एजेंट या फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला संगठित गिरोह सक्रिय है।

दिल्ली हाई कोर्ट से चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका देते हुए को-लोकेशन घोटाला मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी। चित्रा रामकृष्ण ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि एनएसई केवल एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि वह सार्वजनिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य करता है।

जापान से लौटा शख्स का आईजीआई एयरपोर्ट से लापता

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। जापान से लौटे 42 वर्षीय भारतीय नागरिक मोहन प्रसाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं।

देहरादून के अजबपुर कलां निवासी मोहन प्रसाद ने परिवार को 18 मई को भारत आने की बात कही थी, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। शुरूआती जांच में जापानी दूतावास से पता चला कि वे निर्धारित समय से पहले, 28 अप्रैल की रात करीब 11 बजे ही आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है। पति के न मिलने पर पत्नी राखी पैन्यूली ने अपहरण की आशंका जताई है। मामले में पहले देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में जांच के लिए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने भेजा गया।

पुलिस ने अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश और निकासी रिकॉर्ड व मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता लगाने के प्रयास कर रही है।

रेखा गुप्ता की उपस्थिति में आईजीएल, शिक्षा निदेशालय और एहसास एनजीओ के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में शुक्रवार को कैच द रेन पहल के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), शिक्षा निदेशालय और एहसास एनजीओ के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना को लागू किया जाएगा। यह परियोजना आईजीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत संचालित की जाएगी, जिसके माध्यम से स्कूल परिसरों में मौजूदा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ऑडिट, उनका पुनरुद्धार और नए रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

जल संरक्षण सुरक्षित भविष्य की आधारशिला: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। दिल्ली सरकार शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चल रही है। यह पहल सरकारी विद्यालयों में सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। सरकार का लक्ष्य राजधानी के सरकारी विद्यालयों को इतना उत्कृष्ट बनाना है कि भविष्य में अभिभावक निजी विद्यालयों के बजाय सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश कराने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कैच द रेन विजन को दिल्ली में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसी सोच के साथ सरकार ने स्कूलों से इसकी शुरूआत करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल केवल 75 विद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह मॉडल दिल्ली सरकार के लगभग 800 विद्यालयों तक विस्तारित होगा, जिससे राजधानी में व्यापक स्तर पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को स्थापित कर उन्हें पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सरकार, उद्योग और सामाजिक संगठनों के बीच प्रभावी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे न केवल भूजल संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों में जल संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी।

द्वारका बनेगा दिल्ली का आर्थिक हब, निवेश और रोजगार बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। डीडीए ने द्वारका उपनगर को देश की राजधानी का प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में द्वारका को निवेश, रोजगार और आधुनिक शहरी विकास का नया केंद्र बनाने पर चर्चा हुई।

उपराज्यपाल ने कहा कि द्वारका का विकास ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह स्वच्छ, प्रदूषण-मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करें और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती दें। आर्थिक विकास का लाभ सीधे स्थानीय युवाओं और कामगारों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे बड़े नियोजित उप-नगरों में शामिल द्वारका के पास इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और अन्य आधुनिक परिवहन सुविधाओं जैसी बड़ी ताकत है। यह क्षेत्र व्यापार, होटल उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आईटी और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बन सकता है। बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने निवेश बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि बदलती शहरी जरूरतों के अनुरूप फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) सहित विभिन्न विकास नियमों की समीक्षा की जाएगी, ताकि निवेशकों को बेहतर माहौल मिल सके। डीडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण ने भविष्य के निवेश को ध्यान में रखते हुए भूमि उपलब्ध कराई है और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

दिल्ली में जनगणना ड्यूटी का दबाव!

सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में एक सरकारी शिक्षक द्वारा कथित तौर पर जनगणना ड्यूटी के दबाव के कारण आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक को लगातार काम का दबाव और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल शिक्षक का इलाज चल रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से अभी तक आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जनगणना ड्यूटी के दबाव के कारण सरकारी टीचर ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की। परिवार ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित के जीजा विक्रम सिंह तोमर ने बताया कि गुरुवार (9 जुलाई) को शाम करीब 5 बजे हमें इस बात की जानकारी मिली। पुलिस शिक्षक को लेकर हिंदु राव अस्पताल पहुंची। जिसके बाद सेंट स्टीफन अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित शिक्षक अस्थमा के मरीज थे और पिछले 2-2.5 साल से इलाज करवा रहे थे, उन्हें काम पर सीनियर अधिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान किया गया। मेडिकल लीव के लिए आवेदन करने के बावजूद उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई और उन पर काम जारी रखने का दबाव डाला गया। इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण शिक्षक ने स्कूल की इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

हालांकि वे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए, लेकिन परिवार चाहता है कि भविष्य में ऐसी प्रताड़ना को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। विक्रम ने बताया कि वे शास्त्री नगर में रहते थे और एमसीडी के अधीन कार्यरत थे। वे सर्वोदय विद्यालय में शिक्षक थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने कई बार जिक्र किया था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और वे इस समय ड्यूटी के लिए फिट नहीं हैं, लेकिन उन्हें दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

संक्षिप्त वार्ता

खेत से चोरी हुआ इंजन बरामद, आरोपी गिरफ्तार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। अरवल थाना पुलिस ने खेत से चोरी हुए इंजन के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया इंजन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 16 मई को ग्राम हन्नामऊ निवासी बबलू पुत्र चेतराम ने थाना अरवल में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तीन नामजद आरोपियों ने उसके खेत में रखा इंजन चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना अरवल में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान थाना अरवल के उपनिरीक्षक अभय सिंह ने कार्रवाई करते हुए मामले में प्रकाश में आए आरोपी विवेक पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम जकहिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया एक इंजन भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर देख रहे हेल्पर को डीसीएम ने रौंदा, मौत

जलालाबाद (शाहजहांपुर)। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक हेल्पर की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, उड़ीसा से गोविंदगढ़ (पंजाब) जा रहे ट्रक (यूपी 12 बीटी 9695) का टायर चैनेज संख्या 249.400 के पास फट गया था। बिजनौर निवासी 19 वर्षीय हेल्पर आयान पुत्र एजाज नीचे उतरकर टायर देख रहा था। तभी पीछे से आ रही डीसीएम (बीआर 06 जीएच 1373) ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना जलालाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का एसपी ने लिया जायजा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर पुलिस बल की कार्यकुशलता, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की वर्दी, अनुशासन, प्रशिक्षण तथा तैयारियों का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। शासन की मंशा एवं निर्धारित दिशा-निदेर्शों के अनुरूप पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाए। उन्होंने कहा कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय की अपेक्षा लेकर पुलिस के पास आता है, तो उसकी समस्याओं का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान करना प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिससे आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।

कुशीनगर में गलत टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

कुशीनगर 10 जुलाई। कुशीनगर जिले में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को निशाना बनाकर इंटरनेट मीडिया पर गलत टिप्पणी करना पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन को महंगा पड़ा। विहिप कार्यकताओं की शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस ने मामले में आईटी एक्ट व सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने आरोपित को सात दिन के लिए जेल भेज दिया। थाना तुर्कपट्टी के गांव सोहंग के रहने वाले पूर्व जिला पंचायद सदस्य सद्दाम हुसैन ने अपने फेसबुक एकाउंट से बजरंग दल, विहिप व आरएसए को समाज विरोधी संगठन बता एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए पोस्ट की। कुछ ही देर में यह पोस्ट तेजी से क्षेत्र में प्रसारित होने लगा। इसकी जानकारी विहिप कार्यकताओं को हुई तो वे आक्रोशित हो उठे। ब्लाक महामंत्री राजेश कुमार के नेतृत्व में थाने पहुंचे कार्यकताओं ने प्रसारित पोस्ट से जुड़ा प्रमाण सौंप कार्रवाई की मांग की। प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई। तत्काल प्राथमिकि दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। लगभग एक घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपित सद्दाम हुसैन को उसके गांव के चौराहे से गिरफ्तार कर लिया।

12 जुलाई को जनपद में लगेगा 40 लाख पौधे

वेब वार्ता, देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 12 जुलाई को आयोजित होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद को 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यह लक्ष्य विभिन्न विभागों को आवंटित कर दिया गया है तथा सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 12 जुलाई को जनपद में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान का मुख्य थीम ह्यएक पेड़ मां के नामह्ल है। इसके साथ ही जनपद में कुछ विशेष थीम भी लागू की गई हैं। एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले चारागाहों की मेड़ से लगभग तीन मीटर अंदर पौधारोपण कराया जाएगा।

वर्षों पुराने गाटा संख्या 75 भूमि विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम

एसडीएम ने कराई मेड़बंदी : डेढ़ वर्ष पुराने न्यायालय के आदेश का शुरू हुआ अनुपालन

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। बिलग्राम तहसील के ग्राम श्यामपुर मल्लावां स्थित गाटा संख्या 75 से जुड़े वर्षों पुराने भूमि विवाद के समाधान की दिशा में गुरुवार को प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलग्राम स्वयं मौके पर पहुंचे और तहसीलदार तथा राजस्व विभाग की टीम के साथ न्यायालय के लगभग डेढ़ वर्ष पुराने मेड़बंदी आदेश का अनुपालन कराते हुए उपलब्ध भूमि पर मेड़बंदी कराई।कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम ने मौके पर पैमाइश की और अभिलेखों का मिलान किया। इस दौरान यह सामने आया कि राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में त्रुटि होने के कारण पूरी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। अधिकारियों ने बताया कि पहले नक्शा शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, जिसके बाद पुनः पैमाइश कर शेष भूमि का भी नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। फिलहाल उपलब्ध भूमि पर न्यायालय के आदेश के अनुरूप मेड़बंदी की कार्रवाई पूरी कर दी गई है।एसडीएम बिलग्राम ने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्शा शुद्धिकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए, ताकि शेष भूमि का भी नियमानुसार सीमांकन एवं मेड़बंदी कराकर न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मामलों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।

मामले से जुड़े दिवाकर मिश्रा ने बताया कि उन्हें अभी पूरी भूमि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन न्यायालय के आदेश का अनुपालन शुरू होना और एसडीएम बिलग्राम का स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित कराना संतोषजनक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नक्शा शुद्धिकरण के बाद शेष भूमि का भी जल्द निस्तारण होगा और उन्हें पूरा न्याय मिलेगा। दिवाकर मिश्रा ने एसडीएम बिलग्राम की सक्रियता, निष्पक्षता और प्रशासनिक कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से वर्षों से लंबित तथा लगभग डेढ़ वर्ष पहले पारित न्यायालय के आदेश का अनुपालन शुरू हो सका। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से आमजन का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है और यह संदेश गया है कि अधिकारी इच्छाशक्ति के साथ कार्य करें तो वर्षों पुराने विवादों का भी प्रभावी समाधान संभव है। उन्होंने एसडीएम बिलग्राम, तहसीलदार एवं पूरी राजस्व टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

जलालाबाद में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

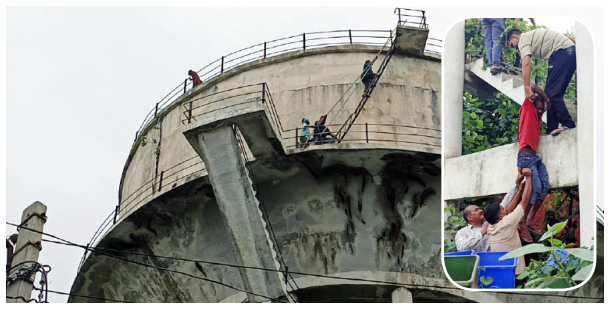

वेब वार्ता, जलालाबाद (शाहजहांपुर)। नगर पालिका जलालाबाद की पानी की टंकी पर शुक्रवार सुबह एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार करीब 11 बजे आसरा आवास निवासी मुकेश पुत्र राम अवतार नगर पालिका की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह टंकी के सबसे ऊपरी हिस्से में सीढ़ी की मचान पर जाकर लेट गया। राहगीरों ने जब उसे देखा तो इसकी सूचना नगर पालिका कर्मचारियों को दी। मौके पर सुपरवाइजर नितिन शर्मा समेत अन्य कर्मचारी पहुंचे और तत्काल पुलिस व तहसील प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और नगर पालिका कर्मचारियों ने काफी देर तक युवक को समझाने का प्रयास किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर लगभग 1:30 बजे उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नशे की हालत में था। उसने बताया कि वह नगर पालिका में पूर्व में संविदा कर्मचारी था और नौकरी से हटाए जाने के विरोध में दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर नगर में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।

ढाई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा

महाप्रबंधक की अनदेखी ने करोडो के वाहन हो रहे क्षतिग्रस्त

वेब वार्ता, कानपुर। उत्तर प्रदेश, संयुक्त वाहन चालक,कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा जलकल विभाग कानपुर से संबंधित आठ बिंदुओं के समस्याओं सहित नए क्रय किए गए वाहनों जो छोटी-छोटी खराबियों में खड़े हैं, उसकी मरम्मत तथा रजिस्ट्रेशन व फिटनेस बीमा कराए जाने का अनुरोध संगठन निरंतर अगाह करता आ रहा है,लेकिन महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने इस ओर कोई भी घ्यान नही दिया। महाप्रबंधक जलकल विभाग द्वारा ध्यान न देने के कारण करोड़ों के वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे है। जिससे सरकार व विभाग को काफी क्षति हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश, संयुक्त वाहन चालक,कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि 27 जून, 2026 को कानपुर के नगर आयुक्त को प्रतिलिपि करते हुए अवगत कराया गया था, कि समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो संगठन शासन को पत्राचार करने में मजबूर होगा बावजूद इसके कोई भी संज्ञान नही लिया। संज्ञान न लेने पर संगठन ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव नगर विकास को पूर्व से संगठन द्वारा दिए जा रहे पत्र को संलग्नक करते हुए पत्र प्रेषित किया है।

मिशन सेफ फ्यूचर अभियान में स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस और परमिट दुरुस्त, अधिकारियों को मिला सम्मान

वेब वार्ता, कानपुर। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ कानपुर नगर के नवीन सभागार, सरसैया घाट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति बैठक-2026 का सफल आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ह्यमिशन सेफ फ्यूचरह्व अभियान के तहत स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना था। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में घाटमपुर विधानसभा की विधायिका श्रीमती सरोज कुरील उपस्थित रहीं और

उन्होंने अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त टीम का गठन कर शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मिलकर एक संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए है कि स्कूलों के बाहर वाहन सुरक्षा मानकों से जुड़े पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे, ताकि स्कूल संचालक और अभिभावक जागरूक हो सकें। सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द सभी मानक पूरे कर लें। एक निश्चित समय सीमा के बाद मानक पूरे न करने वाले वाहनों पर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन कहकशां खातून ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि शासन के निदेर्शानुसार चलाए जा रहे ह्यमिशन सेफ फ्यूचरह्व अभियान के तहत जिले के सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस और परमिट की गहन जांच की गई है। कई वाहनों के चालान काटे गए और सख्त कार्रवाई करते हुए अब शत-प्रतिशत वाहनों की फिटनेस और परमिट को दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि सड़कों पर दौड़ने वाले नौनिहाल पूरी तरह सुरक्षित रहें। अभियान को पूरी निष्ठा और सख्ती से लागू करने के लिए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं घाटमपुर विधायक सरोज कुरील ने परिवहन विभाग की टीम की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने बेहतरीन कार्य करने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन कहकशां खातून और एआरटीओ तृतीय दल सोमलता यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनीं 79 शिकायतें

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में कुल 79 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि फरियादियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान कर संबंधित लोगों को राहत प्रदान की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) दीपाली भार्गव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कासिमपुर पुलिस ने दबोचा 25 हजार का इनामी बदमाश, भेजा जेल

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कासिमपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी को थाना कासिमपुर में उस्मान पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला काजीपुर, कस्बा एवं थाना बिलग्राम सहित छह लोगों के खिलाफ आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित होकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा आरोपी उस्मान की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कासिमपुर पुलिस ने अभियान के दौरान उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बम-बम भोले' के जयकारों के बीच कछौना से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था

भक्तिमय माहौल में क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। भगवान शिव के पवित्र धाम श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए बालामऊ-कछौना से श्रद्धालुओं का एक जत्था शुक्रवार को श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ रवाना हुआ। हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय बाबा बफार्नी के गगनभेदी जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा।

यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जलपान और मिष्ठान कराकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर सत्य प्रकाश मिश्रा, मुकेश सिंह 'गोलू', मोनू दीक्षित सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री अमरनाथ धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की तप, वैराग्य, आत्मशुद्धि और शिव तत्व की अनुभूति का दिव्य केंद्र है। यहां की यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है और जीवन को शिवमय बनाने का संदेश देती है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि आस्था और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है।

अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में रवाना हुए जत्थे में कुलदीप सिंह, विनोद कुमार, रितिक द्विवेदी, हर्ष तिवारी, कारन, आशीष जायसवाल, रोहित सिंह, योगेंद्र पाल, सरोज, विशाल गुप्ता, अश्वनी पांडेय, शिवम शुक्ला, विजयराम, विवेक मंडल, आकाश, पुकित, सुमित सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे। क्षेत्रवासियों ने सभी यात्रियों की सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एसबीआई बैंक की नवीन पहल

जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों के लिए एसबीआई द्वारा बेडसाइड बैंक खाता खोलने की पहल का हुआ शुभारंभ

वेब वार्ता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की लाभार्थी महिलाओं को अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा बेडसाइड बैंक खाता खोलने की अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब जननी सुरक्षा योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही उनके बेडसाइड पर खोले जाएंगे। इससे उन्हें बैंक शाखा के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा योजना की प्रोत्साहन राशि एवं अन्य शासकीय लाभ सीधे उनके खातों में समयबद्ध एवं सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सकेंगे।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एसबीआई की इस अभिनव एवं जनहितैषी पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास डिजिटल इंडिया एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गरीब एवं जरूरतमंद

माताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ प्राप्त होगा तथा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल में ही बैंक खाता खोलने की सुविधा मिलने से लाभार्थियों को अत्यधिक सुविधा होगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा जननी सुरक्षा योजना के लाभ समय पर सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इसे स्वास्थ्य विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण बताया।

कार्यवाहक विभागअध्यक्ष डॉ सीमा द्विवेदी एवं सीएमएस डॉ अनिता गौतम ने इस पहल के सफल संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि यह मॉडल भविष्य में अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा। इस अवसर पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के संयुक्त तत्वावधान में ष्वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशनष विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थी महिलाओं, उनके परिजनों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित बैंकिंग, सरकारी योजनाओं एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में कार्यरत लगभग 400 कर्मचारियों के बीच वित्तीय साक्षरता पर किए गए एक सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

महत्वपूर्ण ख़बर

महंगाई से तंग आकर कपल ने पाया शांति का ठिकाना

■ लंदन। आज की तेज-तर्रार और भागदौड़ भरी जिंदगी में, शहरी जीवन की लगातार बढ़ती लागत, प्रदूषण और दैनिक तनाव ने लोगों को इस कदर थका दिया है कि वे अब प्रकृति की गोद में शांति और सुकून की तलाश में हैं। शहरों का बेतहाशा किराया, सुविधाओं का खर्च और रोजमर्रा का दबाव कई लोगों को एक वैकल्पिक जीवनशैली अपनाने पर मजबूर कर रहा है। इसी कड़ी में, इंग्लैंड के वेल्स के एक युवा जोड़े, लोइस रॉबर्ट्स और एरॉन लॉइड ने एक ऐसा असाधारण कदम उठाया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है और जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। कार्डिफ शहर के निवासी इस जोड़े ने अपनी व्यस्त और महंगी शहरी जिंदगी से तंग आकर एक ऐसा फैसला लिया, जो उन्हें वेल्स के तट से दूर इनिस एनली नामक एक बेहद छोटे और सुदूर द्वीप पर ले आया है, जिसे बार्डसी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।

कोरोना वायरस से मौत, दोनों फेफड़े हो चुके थे खराब

■ नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी हो गई है. आंध्र प्रदेश के कडप्पा में कोरोना वायरस से 46 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है. यह जानकारी जिला मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर रवि बाबू ने गुरुवार को दी. उन्होंने बताया कि मरीज को दवाओं से भी आराम नहीं मिला और चार दिन के इलाज के बाद उसकी जान चली गई. मृतक शराब का आदी था और उसे तेज सांस लेने में दिक्कत और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रवि बाबू ने पीटीआई को बताया कि कडप्पा के मासापेटा इलाके का यह व्यक्ति कोरोना वायरस से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि मरीज शराब पीने का आदी था और उसे सांस लेने में गंभीर तकलीफ के साथ खांसी भी हो रही थी. जब अस्पताल में उसका एक्स-रे किया गया तो पता चला कि उसके दोनों फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे. इस वजह से उसे निमोनिया भी हो गया था. डॉक्टरों ने शुरूआत में मरीज को तेज डोज वाली एंटीबायोटिक दवाएं दीं, लेकिन चार दिन तक इलाज चलने के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं आया.

ट्रंप का ध्यान ईरान जंग पर, पीएम मोदी ने गुपचुप बना दिया 35 देशों का ग्रिड

यह भारत को क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, दुनिया में कहीं न कहीं हंगामा मचा हुआ है। जनवरी, 2025 में सत्ता संभालते ही ट्रंप ने पूरी दुनिया पर ट्रेड टैरिफ लगाकर हंगामा मचा दिया। इस साल फरवरी 2026 में ईरान के साथ जंग करके भारत समेत पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जून 2024 में जब से तीसरी बार सत्ता में आए तो वह गुपचुप एक मिशन पर लगे हुए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि बीते करीब दो साल में पीएम मोदी ने 35 देशों का एक ग्रिड बना लिया, जो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी नींव रख दी थी।

उन्होंने अपने विदेशी दौरों के साथ चुपचाप इस मिशन को पूरा किया। पीएम मोदी ने भारत को 35 देशों के उस ग्रिड से जोड़ दिया, जिनके पास रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। हाल ही में पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। इसका मकसद जरूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन की मजबूती बहुत अहम है। अहम मिनरल्स और स्टील सेक्टर में सप्लाई चेन को और मजबूत करने

के लिए एक जरूरी समझौता हुआ है, जैसे-जैसे साफ ऊर्जा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की ओर दुनिया का झुकाव तेजी से बढ़ रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स वैश्विक भू-राजनीति में एक अहम रणनीतिक संपत्ति के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में भारत के बनाए इस ग्रिड की अहमियत बढ़ जाती है।

क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे संसाधन हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए जरूरी हैं। तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, चांदी के अलावा, रेयर अर्थ एलिमेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल हैं। ये क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस जैसे सेक्टर में अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक बदलाव में भी मदद करते हैं। इन मिनरल्स की सप्लाई चेन में अक्सर रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए देश इनकी भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुर्लभ मृदा समेत कई क्रिटिकल मिनरल्स के वैश्विक प्रसंस्करण में योगदान देता है। वहीं, प्रसंस्करण क्षमता का अनुमानित 80-90 फीसदी हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। वैश्विक कच्चे और प्रोसेस्ड क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 17.6 फीसदी है। वहीं, भारत की हिस्सेदारी करीब 3.3 फीसदी है। रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। ये ऐसे खनिज हैं, जिनके दम पर ही आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस से लेकर न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए जरूरी उपकरण बनाए जा सकते हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भारत ने अपना नेशनल मिशन शुरू किया है, ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

भूकंप से कुछ सेकंड पहले अलर्ट भेज सकता है गूगल का ये फीचर

कारकास। प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व सचेत करने को लेकर आधुनिक तकनीक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसा ही एक गूगल का एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट फीचर है जो भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी भेज सकता है। वेनेजुएला में हाल के दिनों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इस तकनीक की फिर से चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि भूकंप के झटके आने से पहले उनके एंड्रॉयड फोन पर गूगल की ओर से चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ था। साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, अलर्ट में संभावित भूकंप की तीव्रता, दूरी और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई थी। इससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेकंड मिल सके। गूगल का यह सिस्टम पारंपरिक भूकंप मापने

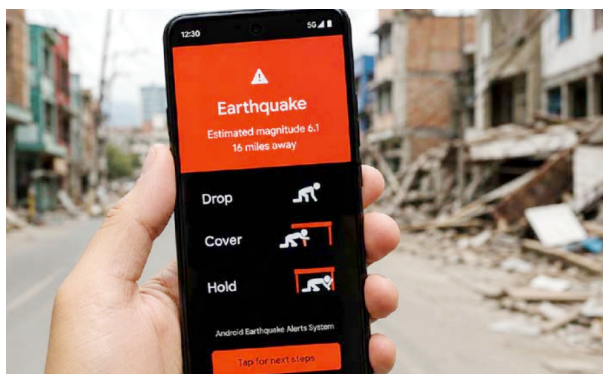

वाले उपकरणों के साथ-साथ दुनिया भर में मौजूद करोड़ों एंड्रॉयड स्मार्टफोन का भी उपयोग करता है।

आधुनिक स्मार्टफोन में लगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर फोन की गति और कंपन को पहचानने में सक्षम होता है। यही सेंसर सामान्य उपयोग के दौरान स्क्रीन को घुमाने या गतिविधियों का पता लगाने का काम करता है। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन एक जैसी असामान्य कंपन दर्ज करते हैं, तो यह जानकारी गूगल के सर्वर तक पहुंचती है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विशेष एल्गोरिद्म यह विश्लेषण करते हैं कि कंपन किसी भूकंप के कारण है या सामान्य गतिविधि के कारण। यदि भूकंप की पुष्टि होती है, तो संभावित प्रभावित क्षेत्र के एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को तत्काल चेतावनी भेज दी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप की तरंगें अलग-अलग गति से यात्रा करती हैं।

तेज गति वाली प्राथमिक तरंगें पहले पहुंचती हैं, जबकि अधिक नुकसान पहुंचाने वाली द्वितीयक तरंगें कुछ सेकंड बाद आती हैं। इसी समयांतराल का उपयोग करते हुए चेतावनी प्रणाली लोगों तक अलर्ट पहुंचाती है, जिससे वे सुरक्षित स्थान पर जाने, गैस और बिजली के उपकरण बंद करने या अन्य आवश्यक सावधानियां अपनाने का प्रयास कर सकते हैं।

गूगल का कहना है कि उसके एंड्रॉयड नेटवर्क से जुड़े अरबों स्मार्टफोन इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। भूकंप की तीव्रता के आधार पर उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग स्तर के अलर्ट भेजे जाते हैं। हल्के झटकों के लिए सामान्य सूचना दी जाती है, जबकि अधिक तीव्र भूकंप की स्थिति में तेज चेतावनी जारी की जाती है, जिससे लोगों को तुरंत सतर्क होने का संदेश मिल सके।

सूर्य ग्रहण और उल्का वर्षा का दुर्लभ संगम

12 अगस्त को अद्भुत कॉस्मिक डबल व्हैमी

नई दिल्ली। 12 अगस्त को आसमान में एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना घटने वाली है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण और उल्का बौछार एक ही दिन देखने को मिल सकते है। वैज्ञानिक इस कॉस्मिक डबल व्हैमी कहते हैं, एक ऐसा संयोग जो सैकड़ों या हजारों सालों में एक बार बनता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सूर्य ग्रहण के लिए विशेष चश्मे आवश्यक हैं।

दिन के समय, चंद्रमा सीधे सूर्य के सामने से गुजरेगा, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूके, आयरलैंड और यूरोप के मुख्य हिस्सों में एक शानदार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर और उत्तरी स्पेन से गुजरने वाले मुख्य रास्ते पर कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा। यूके, आयरलैंड, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के अन्य हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखेगा। भारत में यह

ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य रहेगा क्योंकि तब यहां रात होगी, लेकिन आप विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख पाएंगे। सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से देखना खतरनाक हो सकता है, इस देखने के लिए प्रमाणित सोलर एक्लिप्स ग्लासेस का ही उपयोग करें।

जैसे ही दिन ढलेगा और रात होगी, पृथ्वी स्विफ्ट-टटल धूमकेतु के मलबे से होकर गुजरेगी, जिससे साल की सबसे बेहतरीन पर्सीड उल्का बौछार देखने को मिलेगी। यह घटना उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्सों से देखी जा सकती है, बशर्ते मौसम साफ हो। 12 अगस्त की देर रात से 13 अगस्त की सुबह के बीच प्रति घंटे 60 से 100 तक टूटते तारे दिखाई दे सकते हैं।

एक मीनार के ऊपरी हिस्से को हल्के से हिलाओ, तो दूसरी मीनार में होती है कंपन

सदियों पुरानी झूलती मीनारें आज भी वैज्ञानिकों के लिए बनी हैं रहस्य

नई दिल्ली। भारत की ऐतिहासिक धरोहरें अपनी भव्यता के साथ कई ऐसे रहस्यों को भी समेटे हुए हैं, जिनका आकर्षण आज भी लोगों और शोधकताओं के लिए बना हुआ है।

इन्हीं अनोखी धरोहरों में से एक तेलंगाना के करीमनगर जिले में एलगंदल किले के निकट स्थित सदियों पुरानी दो मीनार मस्जिद है। यह ऐतिहासिक इमारत केवल कुतुब शाही और आसफ जाही शासनकाल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण ही नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी इंजीनियरिंग के कारण भी विशेष पहचान रखती है। इसकी संरचना और तकनीक को देखकर विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित हैं। चारमीनार की तरह यह इमारत भी अपने समय की बेहतरीन कारीगरी और वास्तु कौशल का शानदार नमूना है, जिसे देखने देश-विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने संरक्षित यह ऐतिहासिक मस्जिद प्रसिद्ध एलगंदल किले से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी दो ऊंची और आकर्षक मीनारें हैं।

मीनारों के अंदर बेहद संकरी और घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें बड़े ही सटीक ढंग से तराशे गए पत्थरों से तैयार किया गया है। इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने पर बने झरोखों से एलगंदल किले के साथ आसपास का प्राकृतिक दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है।

हालांकि, इस मस्जिद की सबसे अनोखी पहचान इसकी रहस्यमयी ह्यझूलती मीनारेंह्ल हैं। बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक मीनार के ऊपरी हिस्से को हल्के से हिलाता है, तो कुछ ही क्षणों में दूसरी मीनार में भी कंपन होने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों मीनारों को जोड़ने वाला मुख्य ढांचा पूरी तरह स्थिर बना रहता है। माना जाता है कि यह तकनीक उस समय भूकंप के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। यह अद्भुत संरचना उस दौर के शिल्पकारों और इंजीनियरों की उच्च वैज्ञानिक समझ, तकनीकी दक्षता और निर्माण कौशल का प्रमाण है।

रिपोर्ट के मुताबिक काकतीय शासकों, कुतुब शाही सुल्तानों और हैदराबाद के निजामों के शासनकाल की साक्षी रही यह ऐतिहासिक मस्जिद आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शोधकताओं के लिए अध्ययन का अहम विषय है। प्रशासन ने इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है, ताकि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत स्थापत्य कला और प्राचीन वैज्ञानिक सोच को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जा सके। यह धरोहर आज भी भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट परंपरा और प्राचीन इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल के रूप में लोगों को आकर्षित कर रही है।

न्यूक्लियर से होर्मुज पर टिका अमेरिका-ईरान तनाव

वॉशिंगटन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था, उसके केंद्र में बताया जा रहा था न्यूक्लियर, लेकिन वर्तमान में होर्मुज केंद्र में नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका-ईरान में जारी तनाव अब परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे से आगे बढ़ गया और हकीकत में होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव या जहाजरानी में व्यवधान अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। हालिया घटनाओं के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है और कई शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग पर परिचालन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाणिज्यिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही बनाए रखना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार हालिया हवाई हमले उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जिनसे समुद्री यातायात को खतरा उत्पन्न हो रहा था।

पहले डील फिर धमकी और अब अटैक, क्यों भड़के ट्रंप?

वॉशिंगटन। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, और इसके जवाब में अमेरिका ने 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाने का दावा किया। पहली नजर में यह संघर्ष विराम तोड़ने पर अमेरिका की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन इस कहानी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू भी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जून में जिस संघर्ष विराम और समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, वही समझौता कुछ ही दिनों बाद उनके लिए राजनीतिक बोझ बन गया। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर अमेरिका ने ईरान को इतनी रियायतें क्यों दीं।

इस डील के तहत अमेरिका ने होर्मुज से नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और ईरानी तेल पर अस्थायी राहत देने जैसी रियायतें दीं। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का वादा किया। लेकिन इस डील के आलोचकों का कहना था कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता या प्रॉक्सी नेटवर्क पर कोई ठोस कार्रवाई करने का वादा नहीं किया। इसने ही ट्रंप के लिए राजनीतिक मुश्किलें पैदा कर दीं। टॉम कॉटन, रोजर विकर, बिल कैसिडी, जॉन कॉर्निन और टेड क्रूज जैसे रिपब्लिकन नेताओं ने अलग-अलग शब्दों में इस समझौते पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे अमेरिका की कमजोर सौदेबाजी बताया तो कुछ ने इसे अमेरिकी विदेश नीति का ब्लंडर कहा।

जिस खजाने पर इतराता है ड्रैगन अब उसी पर चोट करेगा भारत

नई दिल्ली। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जबसे ह्यइंडो-पैसिफिकह्ल रणनीति से इंडो शब्द को हटा दिया है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों ने आपसी कूटनीति को एक नई दिशा देना शुरू कर दिया है। इस कूटनीति को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र से जुड़े तीन देशों - इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड - की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा को विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ एक निवारक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल डील पर सहमति बनी है, जिससे चीन बौखला गया है। चीनी मीडिया इसे एक रणनीतिक बदलाव के तौर पर देख रही है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ पृथ्वी खनिज) को लेकर एक महत्वपूर्ण करार होने की संभावना है, इसके अलावा यूरेनियम आपूर्ति को लेकर भी एक डील हो सकती है। वर्तमान में रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का एकाधिकार है, और हाल के महीनों में चीन ने इसके निर्यात पर नकेल कसी है, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स की संभावित डील चीन की मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा साझेदारी और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा

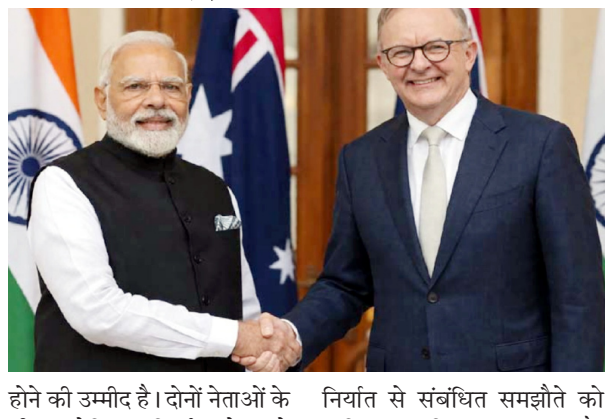

होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच यूरेनियम निर्यात से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच निवेश, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, भारत को यूरेनियम निर्यात से संबंधित समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तक यूरेनियम निर्यात सीमित रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह सुनिश्चित करना रही है कि परमाणु ईंधन का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए ही किया जाए। संभावित समझौते को लेकर पूछे जाने पर प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि इस विषय पर वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ संयुक्त रूप से जानकारी साझा करेंगे और दोनों देश कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाले हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में लगभग दस लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार के रूप में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर थे, जहां दोनों देशों के बीच कृषि, रक्षा और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को न्यूजीलैंड रवाना होंगे और वहां से भारत लौटेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले संभावित रेयर अर्थ मिनरल्स डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, खासकर चीन की इस पर विशेष नजर है। बीजिंग का रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिलहाल एकाधिकार है, और ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), स्मार्टफोन और रक्षा क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना इन उत्पादों का उत्पादन संभव नहीं है। इसके अलावा, सेमी-कंडक्टर उद्योग में भी रेयर अर्थ मिनरल्स की भूमिका काफी अहम होती है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 जुलाई तक

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 12 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक रायपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत फुटबॉल स्पर्धा बालक 15 एवं 17 वर्ष तथा बालिका 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम, कोटा, रायपुर में एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता बालक 14, 17 एवं 19 वर्ष तथा बालिका 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए नेताजी सुभाष स्टेडियम (बॉक्सिंग रिंग), नलघर चौक, रायपुर में आयोजित होगी।

15 व 16 जुलाई को आईटीआई माना में होगी तारमिस्त्री परीक्षा

रायपुर. तारमिस्त्री परीक्षा जुलाई 2026 का आयोजन 15 एवं 16 जुलाई 2026 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), माना, रायपुर में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र तथा अपात्र अभ्यर्थियों के अस्वीकृति सूचना पत्र डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं। परीक्षा से संबंधित पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) तथा संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालय, 246 आम बगीचा, सुंदर नगर, रायपुर के सूचना पटल पर भी चस्पा कर दी गई है।

सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर की परीक्षा 12 मई को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 12 मई को जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे किया जाएगा। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी/उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे। परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 06 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771-2426212 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक - पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारंभ

रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु B.Tech- (कृषि अभियांत्रिकी) एवं B.Tech- (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया पी.ई.टी.-2026, JEE & Mains - तथा 12वीं (गणित समूह) की प्रावीण्य सूची के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम-2026 के अनुसार संपन्न की जाएगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन दिनांक 10 जुलाई से 20 जुलाई (रात्रि 11:00 बजे तक) उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पंजीयन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 23 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प को मिल रही मजबूती

रायपुर. मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इस दिशा में एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुई है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे स्वयं हितग्राहियों से दूरभाष पर संपर्क कर फीडबैक ले रहे हैं। वे शिकायतों के निराकरण के संबंध में नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि प्रत्येक शिकायत का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि स्थायी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम भंवतरा निवासी देवेन्द्र दिनकर ने राशन कार्ड एवं राशन आबंटन से संबंधित समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायत का निराकरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने स्वयं दूरभाष पर उनसे चर्चा कर समाधान की जानकारी ली। श्री दिनकर ने समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। इसी प्रकार पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंडरी निवासी श्री नवीन कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त जारी किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी समस्या का समाधान किया गया। कलेक्टर ने स्वयं उनसे दूरभाष पर चर्चा कर फीडबैक प्राप्त किया। श्री वर्मा ने त्वरित कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक-केंद्रित प्रशासन को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन और शासन के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बनकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सुशासन की भावना को और अधिक मजबूत कर रही है।

लोक निर्माण विभाग राज्य का ग्रोथ इंजन, विभाग पर अधोसंरचना विकसित करने की अहम जिम्मेदारी : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

रायपुर. उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय 'निर्माण भवन' में प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक कार्यों की प्रगति पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद रख कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

श्री साव ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य का %ग्रोथ इंजन% है। राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के साथ ही सभी तरह की अधोसंरचना विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विभाग को भी अहम भूमिका निभाना है। उन्होंने इसके लिए पूरी सक्रियता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को काम का पुराना ढर्रा बदलने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के समय पर बिल तैयार करने और उनका हर महीने भुगतान करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखनी चाहिए। उन्होंने प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यों के लिए समयानुकूल नई कार्यप्रणाली और कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तत्परता से पूर्ण कर आगामी सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि बरसात के तत्काल बाद पूरी गति से काम शुरू हो सके। उन्होंने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूर्ण कर समय पर काम प्रारंभ कराने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि फील्ड पर विभाग के काम और उनके परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने सड़कों और पुल-पुलियों सहित स्कूलों, कॉलेजों, ऑडिटोरियम, कार्यालयों, आवासगृहों एवं अन्य भवनों के निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के साथ अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कर समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा। उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को भू-अर्जन के कार्यों में तेजी लाने इससे संबंधित कानूनों व नियमों की व्यापक एवं समग्र जानकारी के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों तथा उप अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।श्री साव ने पहुंचविहीन गांवों तक साल भर कनेक्टीविटी बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों के प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राथमिकता से तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुराने लंबित कार्यों से जुड़ी समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर काम आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक-लिस्ट करने और उनके अनुबंध टर्मिनेट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ ही द्रुतगामी सड़कों व पुलों, पहुंचविहीन गांवों के लिए पक्की सड़कों, जिले की जरूरतों और विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की प्राथमिकता तय कर आगामी 31 अगस्त तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के काम पूरा होने के बाद तत्काल इन्हें संबंधित विभागों या नगरीय निकायों को हैंडओवर करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंता और सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।

खाद वितरण की नई डिजिटल व्यवस्था शुरू

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए बीजापुर जिले में नई डिजिटल खाद वितरण व्यवस्था शुरू की गई है। भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (एफएफएस) योजना के तहत बीजापुर को पायलट जिले के रूप में चुना गया है। यह नई व्यवस्था 7 जुलाई 2026 से लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत किसान अपने मोबाइल फोन से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (एफएफएस) ऐप के माध्यम से निकटतम उर्वरक विक्रय केंद्र पर खाद की बुकिंग कर सकेंगे।

बुकिंग के बाद उन्हें एक क्यूआर कोड आधारित टोकन मिलेगा, जिसके आधार पर निर्धारित समय पर खाद प्राप्त किया जा सकेगा। जारी किया गया टोकन तीन दिनों तक मान्य रहेगा। यदि किसान इस अवधि में खाद प्राप्त नहीं करते हैं, तो टोकन स्वत: निरस्त हो जाएगा। इससे जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।नई व्यवस्था के पहले चरण में किसान गूगल प्ले स्टोर से एफएफएस ऐप डाउनलोड कर अपनी भूमि और फसल की जानकारी दर्ज करेंगे तथा निकटतम विक्रय केंद्र का चयन कर टोकन प्राप्त करेंगे। दूसरे चरण में किसान विक्रय केंद्र पर क्यूआर कोड आधारित टोकन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद पीओएस मशीन में टोकन स्कैन कर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार इस डिजिटल व्यवस्था से खाद वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। किसानों को समय पर खाद मिलेगी, अनावश्यक भीड़ कम होगी और उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यदि किसी किसान को ऐप का उपयोग करने या टोकन प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, लैम्प्स अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल टोकन आधारित खाद वितरण व्यवस्था किसानों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे खेती के लिए आवश्यक उर्वरक समय पर उपलब्ध होंगे और कृषि कार्यों में तेजी आएगी।

प्रशासनिक डेटा के मानकीकरण से सशक्त होगा सुशासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण

डेटा हार्मोनाइजेशन एवं प्रशासनिक डेटा के सुशासन में उपयोग विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

रायपुर. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज महानदी भवन, नवा रायपुर में Data Harmonization and Use of Administrative Data for Governance" विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शासन के विभिन्न विभागों में उपलब्ध प्रशासनिक डेटा का मानकीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सुशासन तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं नामित नोडल अधिकारियों को नेशनल मेटाडेटा स्टैंडर्ड (NMDS 2.0), स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क (SQAF), विभागीय डेटा कैटलॉग, मेटाडाटा निर्माण, यूनिक आइडेंटिफायर्स, डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन तथा विभागों के मध्य डेटा एकीकरण एवं अंतर-संचालनीयता (Interoperability) से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभागीय डेटासेट के मानकीकरण, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझा करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव ने सभी विभागों के नामित नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए डेटा हार्मोनाइजेशन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला।

धामन सांप और गोह के शिकार के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

रायपुर. वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

वनमंडलाधिकारी कांकेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) के पांच लोगों पर तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार करने का आरोप है। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को एक आरोपी के घर ले जाकर उनके टुकड़े किए गए और भोजन के रूप में उपयोग किया गया। मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता तथा एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वन विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित वन्यजीवों के शिकार, अवैध कब्जे या व्यापार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करें तथा शिकार या वन्यजीव अपराध से संबंधित किसी भी सूचना की तत्काल विभाग को जानकारी दें। वन्यजीवों की सुरक्षा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को मिला 'उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र

रायपुर. जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (CG TRTI) को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र (Certificate of EUcellence) से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ओडिशा के भुवनेश्वर में 07 और 08 जुलाई 2026 को देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRTs) के सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में प्रदान किया गया। कार्यशाला में देश के 29 राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

ई-रिक्शा सहायता का अनुदान बढ़ाकर हुआ एक लाख किया

श्रम मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला: असंगठित श्रमिकों के लिए बनेंगी नई योजनाएं

रायपुर. छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही 50 हजार रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर सीधे एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे श्रमिक आसानी से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे।

डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स), चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए बनेंगी नई योजनाएं असंगठित क्षेत्र के अलग-अलग वर्गों को सुरक्षा देने के लिए मंडल ने अपने दायरे का विस्तार किया है। डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों को अब मंडल के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी। चरवाहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक पृथक (अलग) योजना बनाई जाएगी। असंगठित कर्मकारों के प्रतिभावान व मेधावी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। श्रमिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन के निर्देश

श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन किया जाए, ताकि योजनाओं का सीधा और वास्तविक लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिल सके। उन्होंने पाम्पलेट और चित्रमय बुकलेट के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा हितग्राहियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

इस महत्वपूर्ण प्रथम बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक श्री चैतराम अटामी, विधायक श्री सुशांत शुक्ला, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, अपर श्रमायुक्त एवं नोडल अधिकारी श्री एस.एल. जांगड़े, श्रम विभाग के उप सचिव श्री विपुल गुप्ता सहित वित्त विभाग एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के महाप्रबंधक तथा उप श्रमायुक्त व प्रभारी अधिकारी श्री एस.एस. पैकरा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राज्य श्रम संहिता नियमों संबंधी बैठक आयोजित

रायपुर. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य श्रम संहिता नियमों संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य श्रम संहिता नियमों की अधिसूचना की स्थिति, श्रम विभाग द्वारा केन्द्र का औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम 2026 के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के अधिकारियों को संहिता अंतर्गत राज्य नियम शीघ्र अधिसूचित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने संहिता के क्रियान्वयन हेतु विभागीय पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताओं क्रमश: मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता को लागू किए गए हैं। संहिताओं के प्रभावशील से नियोजकों के विभिन्न श्रम अधिनियमों के अनुपालन के भार में कमी आएगी। उन्हें विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पृथक-पृथक पंजीयन, अनुज्ञप्ति, अभिलेखों के संधारण इत्यादि के स्थान पर एकल पंजीयन तथा कॉमन एवं एकल अनुज्ञप्ति तथा अभिलेखों के संधारण में सुविधा होगी।

संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

मेसी के नाम फीफा विश्वकप में दर्ज हुआ ये अनचाहा रिकार्ड

■ मियाली। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने फीफा विश्वकप फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के क्वार्टर फाइनल तक के सफर में अहम भूमिका निभाई है। मेसी सबसे अधिक गोल के लिए मिलने वाले गोल्डन बूट की दौड़ में भी बने हुए हैं पर इसके बाद भी पैनाल्टी किक पर गोल दागने के मामले में वह फिसड्डी साबित हुए हैं।मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो ने टूनार्मेंट के एक सत्र में दो पेनाल्टी लेने के बाद भी गोल नहीं कर पाये। मिस्र के खिलाफ राउंड ऑफ मुकाबले में भी वह पेनाल्टी को गोल में नहीं बदल पाये।

मेसी फुटबॉल के मैदान पर वह सब कुछ करने में सक्षम रहे हैं जो वे चाहते हैं पर जब भी पैनाल्टी लेने की बात आती है वह पिछड़ जाते हैं जबकि यह फुटबॉल के सबसे आसान शॉट्स में से एक है। मेसी जब पेनल्टी किक लेने के लिए गेंद के सामने खड़े होते हैं तो वे गोल से केवल 12 गज की दूरी पर होते है और उनके पास निशाना लगाने के लिए 196 वर्ग फीट की जगह होती है। इसके साथ ही उनके रोकने के लिए केवल एक गोलकीपर होता है। फिर भी किसी न किसी तरह, यही वह एकमात्र परिस्थिति है जहां उनकी सुपरपावर अचानक उनका साथ छोड़ देती हैं। मेसी का विश्व कप में पेनल्टी किक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। मेसी ने विश्व कप में अबतक कुल 8 पेनल्टी किक लिए हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 4 बार ही गोल में बदला है।

भारत में होगी बिग बैश लीग की शुरूआत, चेन्नई में खेला जाएगा उद्घाटन मैच

नई दिल्ली। कई अटकलों के बीच, अब यह कन्फर्म हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का बहुप्रतीक्षित सीजन 2026-27 भारत में शुरू होगा। सही कहें तो, यह मैच दिसंबर के महीने में चेन्नई के मशहूर एम. चिदंबरम स्टेडियम में होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ इस खबर की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई ढट ने इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते खेल संबंधों का हिस्सा बताया।

डॉब्सन ने अत्रक्ष वीकेंड को बताया, की लोकप्रियता हमारे देश से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने आगे कहा नए मार्केट में अपने गेम को बनाना और फैंस से सच में दमदार तरीकों से जुड़ना हमारी लीग की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के बारे में है। यह हमारे मीडिया राइट्स की वैल्यू, स्पॉन्सर्स के लिए बड़े और बढ़ते ऑडियंस से जुड़ने के मौके, और हमारे प्लेयर्स और हमारे क्लब्स के लिए नए मौके खोजने में दिखता है। इवेंट में, डॉब्सन ने यह भी कहा कि यह इवेंट दोनों देशों के बीच टूरिज्म और बिजनेस लिंक को मजबूत करने में मदद करेगा, साथ ही भारतीय फैंस को इझ्छ का एक्सपीरियंस भी देगा।

उन्होंने कहा, हम यह भी देखना चाहेंगे कि भारत भर से इझ्छ फैंस गेम देखने के लिए चेन्नई आएं। उन्होंने आगे कहा: हम स्टेडियम को भरना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यह बहुत सारे लोगों, रंग, शोर, म्यूजिक और शानदार क्रिकेट के साथ एक सच्चा इझ्छ एक्सपीरियंस हो। हमें लगता है कि यह काफी हिस्टोरिक होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सिर्फ शुरूआत होगी, भविष्य में, भारत में और भी इझ्छ मैच निश्चित रूप से होंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक सीरीज हार पर फूटा फैंस का गुस्सा

सोशल मीडिया पर कोच को हटाने की मांग

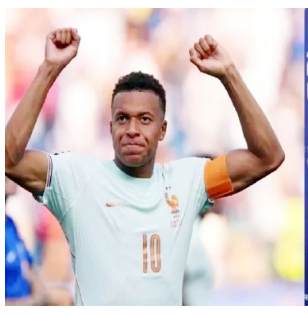

इंग्लैंड के खिलाफ भारत की निराशाजनक श्रृंखला हार के बाद भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर खुद को सोशल मीडिया तूफान के केंद्र में पाया। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली, जो भारत की लगातार दूसरी श्रृंखला हार है। भारत ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद से कोई टी20 सीरीज नहीं हारी थी और 2019 के बाद पहली बार उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। हार के तुरंत बाद, निराश प्रशंसकों ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग की और टीम चयन के कई फैसलों पर सवाल उठाए।

प्रशंसकों के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की चूक थी, कई लोगों ने तर्क दिया कि केरल के बल्लेबाज श्रृंखला में अधिक अवसरों के हकदार थे। कई उपयोगकर्ताओं ने सवाल किया कि भारत के मध्यक्रम के असंगत प्रदर्शन के बावजूद सैमसन को नजरअंदाज क्यों किया गया।

उसी समय, समर्थकों ने तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर के निरंतर समर्थन की आलोचना की, दोनों ने पूरी श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए संघर्ष किया। कई लोगों का मानना था कि बार-बार असफलता के बावजूद यह जोड़ी बनी रही, जबकि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी किनारे पर रहे। आलोचना टीम चयन से आगे तक बढ़ गई, प्रशंसकों के एक वर्ग ने भारतीय टीम प्रबंधन पर हालिया अंतरराष्ट्रीय फॉर्म के बजाय आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को तरजीह देने का आरोप लगाया। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग की बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों ने विदेशी दौरों के लिए भारत की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कई प्रशंसकों के अनुसार, आईपीएल में सपाट पिचों के प्रचलन ने बल्लेबाजों को अंग्रेजी परिस्थितियों द्वारा प्रदान की जाने वाली गति, उछाल और अनुशासन को संभालने के लिए तैयार नहीं किया है।

किलियन एमबाप्पे ने मिस्ड पेनल्टी की भरपाई 'गोल फॉर द एजेस' से की, फ्रांस को दिलाई बड़ी जीत

खेल समाचार। काइलियन एम्बाप्पे हमारी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक हैं और गुरुवार को क्वार्टर-फाइनल गेम में जब फ्रांस और मोरक्को के बीच मुकाबला हुआ, तो उन्होंने एक बार फिर फैंस को अपनी महानता की झलक दिखाई। मोरक्को के खिलाफ गेम के दौरान, एम्बाप्पे को पहले हाफ की शुरूआत में ही पेनल्टी मिली, जब मोरक्को के डिफेंडर नौसेर मजराउई ने उन्हें पेनल्टी एरिया के अंदर गिरा दिया। रेफरी ने श्अफका ऑप्शन चुना और पेनल्टी देने में तीन मिनट लग गए। एम्बाप्पे ने पेनल्टी ली, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर यासीन बौनू के सही अंदाजे और शानदार बचाव के कारण चूक गए।

हालांकि एम्बाप्पे पेनल्टी चूक गए, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना क्लास दिखाया जब उन्हें पहले हाफ के ठीक बाद एक और मौका मिला। एम्बाप्पे ने खुद को शांत रखा और दाएं पोस्ट के अंदर एक शांत फिनिश के साथ अपनी टीम को स्कोरबोर्ड पर ला दिया। इस बार बौनू के पास एम्बाप्पे का कोई जवाब नहीं था।

ओस्मान डेम्बेले ने भी गोल किया और दो बार के चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बाप्पे ने कहा, आराम करने का सिर्फ.एक ही तरीका है, और वह है जीतना। जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, हम हार नहीं मानेंगे। हम सेमीफाइनल में हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।₹ एम्बाप्पे का 60वें मिनट में किया गया गोल उनके वर्ल्ड कप करियर का 20वां गोल था और टूनार्मेंट में उनके 20वें मैच में आया, जिससे वह अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी से एक गोल पीछे हो गए। डेम्बेले ने 66वें मिनट में टूनार्मेंट का अपना पांचवां गोल किया।

एम्बाप्पे 76वें मिनट में जमीन पर गिर गए, लगभग 13 मिनट बाद जब उन्हें एक मोरक्को के डिफेंडर ने जोर से मारा, और एक मिनट बाद उन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। फिर उन्हें बेंच पर बैठे हुए दिखाया गया, उनके दाहिने टखने पर आइस पैक लगा था। मैच के बाद और दोनों जूते पहने हुए, एमबाप्पे अपने टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने के लिए दौड़े और कूदे।

गाजा में इजरायली हवाई हमले में फीफा विश्व कप 2026 स्क्रीनिंग के आयोजक की मौत

गाजा। मोहम्मद अल-वाहिदी, फि लिस्तीनी मदद करने वाले वर्कर, जिन्होंने गाजा में परिवारों के लिए FIFA वर्ल्ड कप की पब्लिक स्क्रीनिंग ऑर्गनाइज की थी, मंगलवार को गाजा शहर में एक इजराइली एयर स्ट्राइक में मारे गए।

65 साल के यह आदमी अपने राहत कामों और कम्युनिटी की कोशिशों की वजह से इस इलाके के सबसे जाने-माने इंसानी काम करने वालों में से एक बन गए थे। उनकी मौत से पूरे इलाके के फि लिस्तीनियों में दुख की लहर दौड़ गई।

इइउ के मुताबिक, लोकल अधिकारियों के मुताबिक, अल-वाहिदी गाजा शहर के सबरा इलाके से एक टैक्सी में जा रहे थे, तभी एक इजराइली मिसाइल ने उन पर हमला कर दिया। इस स्ट्राइक में तीन और लोग भी मारे गए, जिनमें आठ और 10 साल के दो भाई थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, और एक और आदमी था। पीड़ितों को एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। अ’२ङ्क फीं - किलियन एमबाप्पे ने मिस्ड पेनल्टी की भरपाई 'गोल फॉर द एजेस' से की, फ्रांस को दिलाई बड़ी जीत

हाल के हफ़्तों में, अल-वाहिदी

ने गाजा शहर, देर अल-बलाह और अल-मवासी इलाके में त्रळ्ळ्ळ् वर्ल्ड कप मैचों की पब्लिक स्क्रीनिंग ऑर्गनाइज करके बहुत ध्यान खींचा। इन इवेंट्स में सैकड़ों परिवार आते थे और बच्चों को जंग की मुश्किलों से थोड़ी राहत मिलती थी। सोशल मीडिया पर खराब इलाकों के बीच बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रही भीड़ के वीडियो खूब शेयर किए गए। अल-वाहिदी की मौत अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र के राउंड ऑफ 16 मैच की तय स्क्रीनिंग से कुछ घंटे पहले हुई। उनकी मौत की खबर के बाद, सोशल मीडिया पर फि लिस्तीनियों की श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई, जिन्होंने उनके इंसानी काम की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। कई लोगों ने उन्हें मदद बांटने वाले सेंटर और जगह बदलने वाले कैंप में एक जाना-पहचाना चेहरा बताया।

मिस्र के कोच होसम हसन के टूनार्मेंट के दौरान फि लिस्तीनियों के लिए सबके सामने सपोर्ट दिखाने के बाद स्क्रीनिंग और भी अहम हो गईं। हसन ने ऑस्ट्रेलिया पर मिस्र की जीत के बाद फि लिस्तीनी झंडा लहराया और बाद में टीम के वर्ल्ड कप कैंपेन को मिस्र और फि लिस्तीनी दोनों लोगों को डेडिकेट किया। उनकी बातों और हाव-भाव की गाजा में बहुत चर्चा हुई, जहाँ अल-वाहिदी द्वारा ऑर्गनाइज की गई स्क्रीनिंग में मिस्र

कारोबार

बाजार की छलांग; सेंसेक्स 750 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी 24,150 के पार

नई दिल्ली/मुंबई। शुक्रवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली, जिसने दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को गदगद कर दिया है।

बाजार खुलते ही प्रमुख संवेदी सूचकांकों में जोरदार खरीदारी देखी गई, जिससे बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही हरे निशान में काफी ऊपर कारोबार करने लगे। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मजबूत तिमाही नतीजों और दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में निवेशकों की धारणा बेहद मजबूत हुई है, जिससे बाजार में यह बड़ी तेजी दर्ज की जा रही है।

बाजार खुलने के साथ ही बढ़त का क्या आंकड़ा रहा?

कारोबार शुरू होते ही भारतीय शेयर बाजार में भारी लिवाली देखने को मिली। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 750 अंकों से अधिक की बड़ी उछाल के साथ खुला, वहीं एनएसई का निफ्टी 24,150 के स्तर के पार निकल गया। शुरूआती कारोबार

में इन दोनों प्रमुख सूचकांकों ने 0.85 प्रतिशत तक की बढ़त हासिल की। इस तेजी को सबसे ज्यादा बल आईटी इंडेक्स से मिला, जिसमें बाजार खुलते ही दो प्रतिशत की शानदार बढ़त देखी गई।

डॉलर के मुकाबले रुपये का कैसा प्रदर्शन रहा?

शुरूआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 95.32 पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद, डॉलर के कमजोर होने और तेल की कीमतों में नरमी आने से शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में रुपये में यह तेज दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में डॉलर सूचकांक में 0.25 फीसदी की गिरावट आई। यह 100.64 पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 77.75 डॉलर प्रति बैरल पर था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 532.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

पिछले उतार-चढ़ाव से बाजार ने खुद को कैसे संभाला?

शुक्रवार की यह बड़ी उछाल इसलिए भी राहत देने वाली है क्योंकि इससे पहले बुधवार को बाजार में भारी बिकवाली देखी गई थी। बुधवार की उस तेज गिरावट के बाद, गुरुवार को बाजार में रिकवरी यानी सुधार का दौर शुरू हुआ। वैश्विक बाजारों से मिले सहयोग के कारण प्रमुख सूचकांकों ने मामूली सुधार दर्ज किया था। गुरुवार की उस मामूली रिकवरी के बाद निवेशकों की पूरी नजर टीसीएस की तिमाही आय पर केंद्रित थी, जिसने शुक्रवार को बाजार को नई रफ्तार देने में मदद की।

ट्रूकॉलर जैसे एप्स के खिलाफ कारवाई की तैयारी, ट्राई ने सरकार से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ट्रूकॉलर जैसे कॉल प्रबंधन एप के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ट्राई ने परेशान करने वाली और धोखाधड़ी वाली कॉल पर लगाम लगाने के लिए एक मसौदा नियमन जारी किया है। इसमें कॉल प्रबंधन एप को विनियमित करने का प्रावधान भी शामिल है। ट्रूकॉलर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषित झुनझुनवाला ने ट्राई के इस कदम का विरोध किया है।

एक सूत्र ने बताया कि स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए ट्राई ने कॉल प्रबंधन एप के कामकाज को विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। दूरसंचार विभाग के साथ भी बातचीत हुई है। इस मंजूरी से एप और सेवा प्रदाता को अनचाही कॉल्स के मामले में अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। ट्राई ने ड्राफ्ट टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन प्रेफरेंस (तीसरा संशोधन) रेगुलेशंस, 2026 में कॉल प्रबंधन एप के लिए प्रावधान शामिल किए हैं।

प्रस्तावित नियम के अनुसार, परेशान करने वाली कॉल और एसएमएस की पहचान करने वाले

किसी भी कॉल प्रबंधन एप या वैसी ही सर्विस को असली बातचीत के लिए आने वाली कॉल को टैग, ब्लॉक, फिल्टर या किसी तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहिए और न ही कमर्शियल बातचीत के लिए तय नंबर सीरीज से आने वाली इनकमिंग कॉल को रोकना चाहिए। मसौदा नियमन में ट्राई ने 140 (टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए) या 1600 (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा सर्विस या लेनदेन से जुड़ी कॉल के लिए) से शुरू होने वाली नंबर सीरीज से आने वाली कॉल को टैग या ब्लॉक करने का प्रस्ताव दिया है।

ऋषित झुनझुनवाला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कागज पर खास सीरीज जारी करने का इरादा अच्छा लग सकता है, लेकिन 140 और 1600 नंबर सीरीज के जरिए स्पैम कॉल में भारी बढ़ोतरी हुई है। ट्रूकॉलर ने असल में 17 वर्षों से हर दिन करोड़ों भारतीयों की मदद की है और अब वे लोगों तक पहुंचने वाली भरोसेमंद जानकारी को सेंसर या दबाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि 140/1600 नंबर सीरीज से आने वाली स्पैम कॉल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। हर दिन इन दोनों सीरीज से आने वाली 5.1 करोड़ से अधिक कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि ट्राई का सरकार से मंजूरी मांगने का अनुरोध बिल्कुल बेमतलब है। हम ऐसे अच्छे लोग हैं जो हर दिन करोड़ों भारतीयों (जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं) को भरोसेमंद बातचीत का अनुभव पाने में मदद कर रहे हैं। इसके बजाय, वे बुरे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं और कम्युनिटी की जानकारी को सेंसर करके उन्हें हमें स्पैम और स्कैम करने का खुला मौका देना चाहते हैं। हमें यह मंजूर नहीं है। सजा बुरे लोगों को मिलनी चाहिए, न कि ट्रूकॉलर जैसे उन लोगों को जो समाज पर बहुत अच्छा असर डालते हैं।

स्मार्टफोन-लैपटॉप हो सकते हैं सस्ते

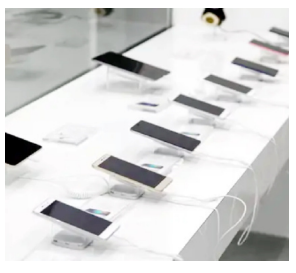

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और वियरेबल डिवाइसेज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई अहम कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (इउऊ) खत्म कर दी है। इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग लागत घटेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिल सकते हैं। सरकार ने डिस्प्ले असेंबली, लीथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान को ड्यूटी फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और उत्पादन लागत कम करना है।

नई ड्यूटी-फ्री सूची में इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाली कई मशीनों को भी शामिल किया गया है। इनमें पाउडर ड्रायर, ऑटोमैटिक फीडिंग एवं ब्लेंडिंग सिस्टम, स्लरी ट्रांसफर सिस्टम, कैथोड-एनोड कोटिंग मशीन, हाई वैक्यूम पंप, वाइंडिंग मशीन, इलेक्ट्रोड कटिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, ऑटो पैकिंग सिस्टम और स्टैकिंग मशीन जैसे उपकरण शामिल हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक ने किया आष्टा सांदीपनि स्कूल का निरीक्षण

- सीहोर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चंद्र ने मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान गुरुवार को सीहोर जिले के आष्टा स्थित सांदीपनि स्कूल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां देखीं और कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संगीत कक्ष, कंप्यूटर कक्ष एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। इस दौरान डीपीसी रमेशराम उईके सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित थे।

18 दिन में तीन दुर्गम धार्मिक यात्राएं पूरी कर नागदा के युवक ने पेश की मिसाल

- नागदा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा निवासी मुकेश विश्वकर्मा ने महज 18 दिनों में तीन कठिन धार्मिक एवं पर्वतीय यात्राएं पूरी कर आस्था, साहस और दृढ़ संकल्प का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। बर्फीले रास्तों, कम ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ी मार्गों को पार करते हुए उन्होंने बुलाकांडा धाम, कैलाश क्षेत्र और श्रीखंड महादेव की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की।

भोपाल में जनवरी से अब तक मलेरिया के चार, डेंगू के 44 और चिकुनगुनिया के मिले 9 मरीज

- भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया लगातार पैर पसार रहा है। यहां जनवरी से अब तक मलेरिया के चार, डेंगू के 44 और चिकुनगुनिया के 9 मरीज मिल हैं। जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू-चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए मलेरिया कार्यालय द्वारा जनवरी से अब तक दो लाख 24 हजार 434 घरों का सर्वे किया गया। जिसमें 5269 घरों मे लार्वा पाया। इस दौरान 16 लाख 47 हजार 992 कंटेनरों में लार्वा की जांच की गई, जिसमें 5776 कंटेनरों में लार्वा पाया गया। 2181 कंटेनर खाली कराए गए एवं 3595 कंटेनरों में लार्वी साइट दवा डाली गई।

उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक 1 लाख 21 हजार 39 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 4 पाजिटिव पाए गए, जबकि 2 हजार 7 सौ 30 संभावित डेंगू मरीजों की जांच में 44 पाजिटिव पाए गए। इसी तरह 615 संभावित चिकुनगुनिया मरीजों की जांच में 9 पॉजिटिव पाए गए।

किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही मिलने लगेगी पर्याप्त बिजली

कृषि और कृषक कल्याण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 'कृषि और कृषक' सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हैक्टेयर से अधिक पहुंच गया है, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 30.86 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 01 करोड़ 45 लाख 56 हजार रुपए की लागत के 04 कार्यों का भूमि पूजन और 29 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपए लागत के 8 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सम्मेलन में किसान भाइयों ने भावांतर भुगतान योजना एवं केसीसी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का गजमाला से साथ ही हल भेंटकर एवं महिला किसानों ने राखी बांधकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधा भी लगाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उपस्थित अतिथियों ने एक पेड़ माँ के नाम, हर भरा कालापीपल अभियान अंतर्गत 04 लाख पौधे रोपण के लक्ष्य अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी प्रांगण में पौध-रोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौध-रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जनभागीदारी से पौध-रोपण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कालापीपल क्षेत्र 04 लाख पौधे रोपित करने के लक्ष्य का यह वृक्ष गंगा अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौपालकों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत अब तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित विभिन्न नदी जोड़ो योजनाओं से लाखों हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे शाजापुर सहित अनेक जिलों के किसानों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शाजापुर जिले के प्रत्येक गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए रात में खेतों पर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से किसानों को दिन के समय ही सिंचाई के लिये विद्युत उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अब खरीफ और रबी फसल के लिए अलग-अलग ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार कृषि लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उद्योगों में बड़े निवेश के साथ युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचनात्मक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकास कार्यों में सहभागी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में शाजापुर जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शाजापुर जिला मेडिकल शिक्षा, आयुर्वेदिक और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का हब बनने जा रहा है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि शाजापुर में मेडिकल कॉलेज व शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात तथा कई सांदीपनि विद्यालय शाजापुर जिले में बनाए जा रहे हैं, इससे शाजापुर जिले के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

क्षेत्रीय सांसद श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर विकास के कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में किये जा रहे नए-नए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। कालापीपल विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी एवं डॉ. रवि पांडे ने भी सभा को संबोधित किया।

विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को कालापीपल के सम्मेलन में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल ग्राम भैसायागढ़ा में अतिरिक्त कक्ष 5, बॉयलॉजी, केमेस्ट्री एवं फिजिक्स लेब निर्माण लागत 01 करोड़ 07 लाख 31 हजार रुपए, वार्ड नं. 07 में टीन शेड निर्माण कार्य लागत 9 लाख 22 हजार रुपए, टीन शेड निर्माण वार्ड नं. 01 में कार्य लागत 17 लाख 52 हजार रुपए, वार्ड नं. 04 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य लागत 11 लाख 51 हजार रुपए इस प्रकार कुल 01 करोड़ 45 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 06 ग्राम पंचायतों कुमेर, कोलबा, मोहम्मदपुर मछनई, कमालपुर, कांकरिया, गणेशपुर में अटल पंचायत भवन निर्माण, 25 लाख रुपए लागत के सामुदायिक भवन नांदनी, 2 करोड़ 95 लाख 45 हजार रुपए लागत के ग्राम खरदौनकलां ब्लॉक कालापीपल में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन मय जी-01 एवं 01 एच टाईप आदि आवासगृहों का निर्माण, 6 करोड़ा 89 लाख 08 हजार रुपए लागत के शुजालपुर आष्टा मार्ग से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग (पुल कार्य चैनेज क्रमांक 5900 मीटर), 11 करोड़ा 69 लाख 61 हजार रुपए लागत के भैंसायागढ़ा से पिपल्या नगर मार्ग (पुल कार्य चैनेज क्रमांक 18700 मीटर), 2 करोड़ 95 लाख 45 हजार रुपए लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरदौनकलां, 2 करोड़ 31 लाख 17 हजार रुपए लागत के खेजड़िया स्टॉप डेम काम काजवे (बैराज), 9 लाख 16 हजार रुपए लागत के वार्ड में 03 आंगनवाड़ी भवन इस प्रकार कुल 29 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपए लागत के कार्यों का लोकार्पण किया। सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया, नगर परिषद कालापीपल अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल, नगरपालिका शुजालपुर अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार, ऊर्जा विकास निगम पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक श्री जसवंत सिंह हाड़ा, प्रसिद्ध कथावाचक संत श्री गोविंद जाने, कथावाचक रामस्वरूप मनावर, श्री महा मंडलेश्वर कल्याणदास जी महाराज, श्री अम्बाराम कराड़ा, श्री अशोक नायक, श्री श्याम टेलर, श्री विजय बैस, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, एडीजी श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

रोड शो में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया अभिवादन, हुआ जगह-जगह भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को कालापीपल में रोड शो कर जनता का अभिवादन किया। नगरवासियों ने उनका जगह-जगह ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया। पूरे मार्ग पर नागरिकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रोड शो नायरा पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर सभा स्थल तक पहुंचा। मार्ग में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों तथा आमजन ने जगह-जगह स्वागत मंच बनाकर मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट, पुष्प हार एवं पारम्परिक साफा बांधकर हार्दिक अभिनन्दन किया। बैंड-बाजों की मधुर धुनों और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री का नागरिकों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

अनूपपुर में झमाझम बारिश से किसानों को राहत, खरीफ बोवनी ने पकड़ी रफ्तार

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मानसून की सक्रियता के चलते जिला मुख्यालय सहित कोतमा, जैतहरी, भालूमाड़ा, अमरकंटक और राजेंद्रग्राम समेत ग्रामीण अंचलों में लगातार हो रही बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

पिछले पांच दिनों से तेज और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद गुरुवार को दिनभर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि तेज बारिश थमने से नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और लोगों को राहत मिली।

वहीं आसमान में काले बादल छाए रहने से आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।

अधीक्षक भू-अभिलेख विभाग के अधिकारी प्रदीप मोगरे ने बताया कि 1 जुलाई से जिले में लगातार वर्षा हो रही है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति है। इस बारिश से जैतहरी, कोतमा, फुनगा, राजेंद्रग्राम और अमरकंटक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई ने गति पकड़ ली है। खेतों में पर्याप्त नमी बनने से किसानों को बुवाई में सुविधा मिल रही है। हालांकि जिले के कुछ इलाकों में अभी भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के कारण किसान सिंचाई पर निर्भर हैं।

1 जून से अब तक जिले में कुल 229.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य औसत वर्षा 279 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 347.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस वर्ष अब तक की वर्षा सामान्य औसत और पिछले वर्ष दोनों की तुलना में कम बनी हुई है।

खरीफ बोवनी अभी 26 प्रतिशत

कृषि विभाग के अनुसार जिले में खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य 1 लाख 85 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक केवल 26 प्रतिशत क्षेत्र में ही बोवनी हो सकी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो बोवनी का कार्य तेजी से पूरा होने की संभावना है।

कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए स्कॉटलैंड रवाना हुई मध्यप्रदेश की अंजली सिंह और माही लामा

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की प्रतिभाशाली महिला मुक्केबाज अंजली सिंह (57 किग्रा) एवं माही लामा (60 किग्रा) का चयन 10 से 24 जुलाई 2026 तक ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी आज स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुईं। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में वे विभिन्न देशों के शीर्ष मुक्केबाजों के साथ अभ्यास कर अपनी तकनीकी क्षमता, फिटनेस एवं प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को और अधिक सशक्त बनाएंगी।

कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करेगा, जहां उन्हें अनुभवी विदेशी कोचों के मार्गदर्शन के साथ विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के विरुद्ध अभ्यास का अवसर मिलेगा। यह शिविर आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ खिलाड़ियों के तकनीकी एवं मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी देश की अग्रणी खेल अकादमियों में शामिल है। आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन, वैज्ञानिक फिटनेस कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के कारण अकादमी ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी तैयार किए हैं। अकादमी प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अंजली सिंह एवं माही लामा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, "मध्यप्रदेश की दोनों प्रतिभाशाली मुक्केबाजों का कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए चयन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह अवसर उनके खेल कौशल को और अधिक निखारने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि दोनों खिलाड़ी इस प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाते हुए आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी तथा देश और मध्यप्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगी।" मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सतत प्रयासों से खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अधोसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को नई पहचान दिला रहे हैं।

ओंकारेश्वर में स्थापित एकात्मता की मूर्ति (स्टैच्यू ऑफ वननेस) पूर्णतः सुरक्षित और सुदृढ़

देश की अग्रणी कंपनी मैसर्स एल एंड टी ने किया है प्रतिमा का निर्माण

भोपाल। पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में 'एकात्म धाम' में स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची बहुधातु प्रतिमा– 'एकात्मता की मूर्ति' पूर्णतः सुरक्षित, सुदृढ़ और संरचनात्मक रूप से अत्यंत मजबूत है।

संस्कृति विभाग के 'आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास' द्वारा वर्ष 2023 में स्थापित की गई यह भव्य प्रतिमा अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके निर्माण, अभिकल्पना और सुरक्षा आकलन में देश-विदेश की सर्वोच्च और अत्यंत प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएँ ली गई हैं।

मुख्य अभियंता एवं परियोजना संचालक एकात्मधाम श्री राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ऐतिहासिक प्रतिमा 'एकात्मता की मूर्ति' का निर्माण कार्य मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का सफलतापूर्वक निर्माण करने वाली देश की अग्रणी कंपनी मैसर्स एल एंड टी (छ&ळ) के माध्यम से संपन्न कराया गया है। मूर्ति के कॉस्टिंग का महत्वपूर्ण कार्य भी 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जैसी वैश्विक धरोहर बनाने वाली ख्याति प्राप्त कंपनी जेटीक्यू द्वारा किया गया है। परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी मैसर्स माइनहार्ट सिंगापुर ने अपनी सेवाएँ दी हैं, जिन्हें इस प्रकार की विशाल संरचनाओं का व्यापक वैश्विक अनुभव है। साथ ही, प्रतिमा के डिजाइन सलाहकार के रूप में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर 'यशोभूमि', 'भारत मंडपम' और 'वल्लभ भवन एनेक्सी' जैसी महत्वपूर्ण शासकीय व राष्ट्रीय इमारतों को स्वरूप देने वाली प्रतिष्ठित फर्म मैसर्स सी.पी. कुकरेजा एसोसिएट्स ने भूमिका निभाई है।

प्रतिमा के संरचनात्मक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (क्कळ) चेन्नई (मद्रास) एवं क्कळ दिल्ली जैसी सर्वोच्च संस्थाओं से विस्तृत तकनीकी परामर्श प्राप्त किया गया है। प्रतिमा का मिक्स डिजाइन और अत्याधुनिक 'सीजमिक एनालिसिस' (भूकंपीय विश्लेषण) जैसे अत्यंत संवेदनशील परीक्षण क्कळ मद्रास द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (क्कळ) दिल्ली द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के अनुसार, इस भव्य प्रतिमा की 'डिजाइन लाइफ' (अभिकल्पना अवधि) 500 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है, जो इसके दीर्घकालिक स्थायित्व को अकाट्य रूप से प्रमाणित करती है।

'एकात्मता की मूर्ति' की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए ओंकारेश्वर कार्य स्थल के सीजमिक जोन-क्कळ में होने के बावजूद, प्रतिमा की संरचनात्मक गणनाएँ अत्यधिक संवेदनशील और उच्चतर सीजमिक जोन-क्कश के कड़े मानकों के आधार पर की गई हैं। इन कठोर पैमानों पर भी प्रतिमा की डिजाइन पूर्णतः सुरक्षित और अचूक पाई गई है। इसी क्रम में, विश्व विख्यात जर्मन विंड इंजीनियरिंग कंपनी मैसर्स वर्नर सोबेक एजी द्वारा प्रतिमा का व्यापक 'विंड टनल एनालिसिस' किया गया है। ओंकारेश्वर क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक वायु दबाव (140 किमी/घंटा) की तुलना में इस प्रतिमा की गणना 169 किमी/घंटा की अत्यधिक उच्च वायु गति पर की गई है, जो विपरीत से विपरीत मौसम में भी इसके अडिग रहने की गारंटी देती है।

विश्वस्तरीय स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर 'एळअइर' के माध्यम से किए गए वास्तविक सॉफ्टवेयर विश्लेषण में भी प्रतिमा की वास्तविक सुदृढ़ता स्थापित हुई है। स्वीकृत एवं अनुमोदित डिजाइन के अनुक्रम में, अनुमेय स्ट्रेस रेशियो की निर्धारित सीमा 0.85 के विरुद्ध इस भव्य संरचना का वास्तविक स्ट्रेस रेशियो मात्र 0.4 पाया गया है, जो कि तय मानकों से बहुत बेहतर और पूरी तरह सुरक्षित सीमा के भीतर है।

तकनीकी विशेषज्ञों और परियोजना अधिकारियों के अनुसार, 'एकात्मता की मूर्ति' का पेडेस्टल (पिलर) और मुख्य ढांचा पूरी तरह से अपने निर्धारित अक्ष पर मजबूती से स्थिर है। यह भव्य प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित, सुदृढ़ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित है, जो आने वाली कई सदियों तक देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बनी रहेगी।

पुलिस सैलरी पैकेज योजना से दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिला आर्थिक संबल

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुलिस सैलरी पैकेज (ढरढ) योजना के अंतर्गत जिला दमोह में पदस्थ दिवंगत दो पुलिसकर्मियों के आश्रित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा दावा राशि प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलादगी ने दिवंगत प्रधान आरक्षक श्रीमती शमीम खान एवं दिवंगत आरक्षक श्री भूपेंद्र ठाकुर के आश्रित परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। दिवंगत प्रधान आरक्षक श्रीमती शमीम खान एवं आरक्षक श्री भूपेंद्र ठाकुर का जून 2025 में दुर्घटना के उपरांत उपचार के दौरान दुखद निधन हो जाने पर उनके वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में पुलिस सैलरी पैकेज योजना से संबद्ध होने के कारण उनके नामांकित उत्तराधिकारी को दुर्घटनावश मृत्यु बीमा के रूप में 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।